सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार
*"वक्त और विश्वास दोनों अनमोल है,
एक चला जाए तो लौटता नहीं,
दूसरा टूट जाए तो जुड़ता नहीं ...!!"*
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–171 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 10 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

बीएसपी से संगठित स्क्रैप चोरी का भंडाफोड़ : पुरानी भिलाई पुलिस की कार्रवाई

2 और आरोपी गिरफ्तार, कुल 15 सलाखों के पीछे, 3 करोड़ 22 लाख की संपत्ति जब्त, गिरोह पिछले 4–5 माह से कर रहा था चोरी

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट से संगठित रूप से लौह स्क्रैप चोरी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अब तक इस प्रकरण में कुल 15 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी बीएसपी से फ्लू डस्ट परिवहन के दौरान योजनाबद्ध तरीके से लौह स्क्रैप की चोरी कर रहे थे और उसे अवैध रूप से बेचकर आर्थिक लाभ कमा रहे थे।

कैसे हुआ खुलासा

26 मई 2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम अकलोरडीह खदानपारा स्थित ए.के. ट्रेडर्स, प्लॉट क्रमांक–18, एच.आई.ए. हथखोज में छापा मारा गया। यहां विभिन्न हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ लोहे की प्लेट, बीम और कटिंग सामग्री भरी मिली। साथ ही बड़ी मात्रा में लौह स्क्रैप अलग–अलग ढेरों में रखा था।

जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले 4–5 माह से बीएसपी का स्क्रैप चोरी कर इस गोदाम में जमा कर रहे थे। मौके से लगभग 250 टन लौह सामग्री जब्त की गई। स्क्रैप लोडिंग और परिवहन में इस्तेमाल हाईवा, ट्रक, जेसीबी, हाइड्रा और 5 मशीनें भी सीज की गईं।

गिरफ्तार आरोपी : एमएमएस तीन के जीएम हिमांशु भूषण मलिक, 54 वर्ष, निवासी भिलाई और एजीएम मनोज कुमार देवांगन, 58 वर्ष, निवासी रिसाली शामिल हैं।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने कहा कि संगठित चोरी और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उक्त कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई की टीम और तकनीकी सहयोग देने वाले कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

अब तक 15 गिरफ्तार, करोड़ों की जब्ती

विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पूर्व में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब बीएसपी के दो अन्य कमर्चारियों की संलिप्तता मिलने पर हिमांशु भूषण मलिक, 54 वर्ष, निवासी भिलाई और मनोज कुमार देवांगन, 58 वर्ष, निवासी रिसाली को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अब तक लगभग 90 लाख रुपये का लौह स्क्रैप और वाहनों सहित कुल 3 करोड़ 22 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

बीएसपी स्क्रैप चोरी कांड : 3 आरोपी जेल भेजे गए
3 करोड़ की संपत्ति–50 लाख के गहने किए जब्त
लॉकर से मिले दस्तावेज, फर्जी नंबर प्लेट से करते थे परिवहन, अब तक 12 गिरफ्तार

250 टन लौह स्क्रैप बरामदगी के बाद फरार आरोपियों की तलाश तेज

- स्क्रैप चोरी मामले पर सेल मुख्यालय की नजर, बीएसपी में 3 कर्मचारी निलंबित
- पुलिस ने एके ट्रेडर्स से बरामद किया करोड़ों का स्क्रैप, सिंडिकेट का हुआ खुलासा

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से करोड़ों रुपए के लौह स्क्रैप चोरी मामले में अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कॉरपोरेट कार्यालय ने भी संज्ञान लिया है। सूत्रों के अनुसार पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट सेल मुख्यालय ने तलब की है और कॉरपोरेट विजिलेंस भी अपने स्तर पर गोपनीय जांच कर रही है।

बीएसपी प्रबंधन फिलहाल मामले पर आधिकारिक बयान देने से बच रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद बीएसपी स्तर पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

250 टन स्क्रैप बरामद, सिंडिकेट का खुलासा

दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर एटीएस और भिलाई–3 थाना पुलिस ने ग्राम अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स में छापेमारी कर करीब 250 टन लौह स्क्रैप बरामद किया था। आरोप है कि फ्लू डस्ट की आड़ में करोड़ों रुपए मूल्य का लौह स्क्रैप प्लांट से बाहर निकाला जा रहा था।

इस बरामदगी के बाद पुलिस को कथित चोरी के सिंडिकेट का सुराग मिला।

बीएसपी के 3 कर्मचारी निलंबित

बीएसपी प्रबंधन ने आंतरिक विजिलेंस जांच के आधार पर एसएमएस–3 विभाग के तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मचारियों में जीएम हिमांशु भूषण मालिक, नॉन–एग्जीक्यूटिव धनंजय वर्मा और मनोज कुमार देवांगन शामिल हैं। प्रबंधन का कहना है कि विस्तृत जांच जारी है और निष्कर्ष के आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी।

अधिकारियों और सीआईएसएफ जवानों से पूछताछ

जांच के दौरान बीएसपी के जीएम, इंजीनियर एसोसिएट, अन्य अधिकारियों तथा सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सीआईएसएफ के एक एसआई और दो हेड कॉन्स्टेबल के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब पुलिस संदेह के दायरे में आए अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच तीन राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में चल रही है। साक्ष्य मजबूत करने के लिए तीन लोक अभियोजकों की कानूनी राय भी ली जा रही है। सीआईएसएफ के आधा दर्जन जवानों से भी पूछताछ की तैयारी है।

फरार आरोपियों की तलाश में दबिश

मामले के प्रमुख आरोपी अब भी फरार हैं। हिमांशु ब्रदर्स के संचालक हिमांशु खंडेलवाल के विदेश भाग जाने की आशंका है। इसके अलावा आरडीके के संचालक गिरीश खंडेलवाल, ट्रांसपोर्टर अभय सिंह और गोदाम मालिक सलीम भी फरार बताए जा रहे हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम अब तक उनके परिचितों समेत आधा दर्जन से अधिक संभावित ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होते ही मामले में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

26 करोड़ के रेल ओवरब्रिज में दरारें

डॉ. रमन सिंह ने रेलमंत्री को लिखा पत्र, उच्च स्तरीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग

सांध्य दैनिक नई दृष्टिबिंदु
26 करोड़ के ओवरब्रिज पहली बारिश में बैठे!, बरगा–आलीवारा–मुसरा में दरारें, सड़क धंसी

लोकार्पण के 15 दिन बाद ही पुल में 70 फीट लंबी दरार, सुरक्षा पर सवाल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर–राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले में बने बरगा–आलीवारा–मुसरा रेल ओवरब्रिज में आई दरारों को लेकर केंद्र सरकार से कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस घटना से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों में गहरी चिंता और नाराजगी है। उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि मामले की तत्काल उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। साथ ही निर्माण एजेंसी, ठेकेदार, परामर्शदाता और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

सुरक्षा परीक्षण और मरम्मत की मांग

विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी मांग की है कि ओवरब्रिज का तत्काल सुरक्षा परीक्षण कराया जाए और जरूरत के अनुसार मरम्मत की जाए, ताकि किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

लोकार्पण के बाद ही दिखीं दरारें

डॉ. रमन सिंह ने पत्र में बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन के नागपुर मंडल अंतर्गत डोंगरगढ़–राजनांदगांव रेलखंड पर ग्राम बरगा, आलीवारा एवं मुसरा के पास प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से रेल ओवरब्रिज बनाया गया था। इसका लोकार्पण जून 2026 में हुआ था। लेकिन 4 और 5 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद पुल में 60 से 70 फीट लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें दिखाई दी हैं। लोकार्पण के कुछ ही दिनों में इस तरह की क्षति सामने आने से पुल की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

महादेव सट्टा ऐप केस में CBI का मेगा एक्शन

6 चार्जशीट दाखिल, 66 आरोपियों पर शिकंजा

सौरभ–रवि समेत बड़े नाम शामिल, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोटेक्शन मनी और विदेश से संचालन का खुलासा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6 चार्जशीट अदालत में दाखिल की हैं। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और अवैध सट्टेबाजी से जुड़े 66 आरोपी शामिल हैं। CBI के मुताबिक चार्जशीट दो हिस्सों में दाखिल की गई हैं।

भ्रष्टाचार वाले मामले में 6 पर आरोप

भ्रष्टाचार से जुड़े पहले मामले में असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के खिलाफ PC Act 1988 और IPC के तहत चाजर्शीट पेश की गई है। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। इस मामले में महादेव ऐप के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ भी अतिरिक्त साक्ष्य कोर्ट में सौंपे गए हैं।

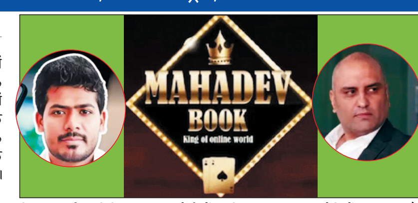

सट्टेबाजी सिंडिकेट में 66 आरोपी

दूसरे मामले में CBI ने 66 आरोपियों के खिलाफ 5 अलग–अलग चाजर्शीट दाखिल की हैं। इसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और बेटिंग सिंडिकेट के कई पैनल सदस्य शामिल हैं। इनके जरिए अवैध सट्टेबाजी से कमाई गई रकम का लेन–देन किया जाता था। आरोपियों पर IPC और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

विदेश से चलता था नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल

CBI की जांच में सामने आया कि महादेव ऐप देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक है, जिसे भारत के बाहर से संचालित किया जाता था। सौरभ और रवि ने सोशल मीडिया के जरिए देशभर में लाखों यूजर्स जोड़े। सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को 'म्यूल अकाउंट्स' के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर विदेश भेजा जाता था। जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि अपराध से अर्जित धन का एक हिस्सा सरकारी अधिकारियों को 'प्रोटेक्शन मनी' के रूप में भी दिया जाता था।

4 आरोपियों पर रेड कॉर्नर नोटिस

उइकने बताया कि विदेश में छिपे 4 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

एजेंसी ने कहा कि महादेव ऐप सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क, उसे मिले कथित राजनीतिक और नौकरशाही संरक्षण और अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है। जरूरत पड़ने पर आगे और चार्जशीट भी दाखिल की जाएंगी।

दक्षिण अफ्रीका में छत्तीसगढ़ के जयदीप साहू ने रचा इतिहास

पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोहरे स्वर्ण पदक के साथ बने भारत के धुरंधर

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र जयदीप साहू ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया–पेसिफिक अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रच दिया है। जयदीप ने एक ही टूर्नामेंट में दो स्वर्ण पदक जीतकर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मंच पर गौरवान्वित किया। यह प्रतियोगिता 4 से 12 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही है।

दोनों कैटेगरी में स्वर्ण

जयदीप ने टूर्नामेंट के पहले चरण में 6 जुलाई को इक्विप्ड कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद दूसरे दौर की क्लासिक (UNEQUIPPED) प्रतियोगिता में 66 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। इस तरह जयदीप भारत के लिए दोहरा स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने।

15 साल की मेहनत का नतीजा

जयदीप ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से प्राकृतिक खानपान और अनुशासन के साथ अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में कई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन बिना किसी शक्तिवर्धक दवा के सिर्फ देसी पौष्टिक आहार और मेहनत से भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण जीता जा सकता है। उन्होंने अपने दोनों स्वर्ण पदक भारत के वीर जवानों को समर्पित किए हैं।

पिता कृष्णा साहू बने सारथी

जयदीप की इस सफलता के पीछे उनके पिता और कोच कृष्णा साहू का बड़ा योगदान है। कृष्णा साहू स्वयं अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टर, भारतीय टीम के कोच और अंतरराष्ट्रीय निर्णायक रह चुके हैं। वे विक्रम पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार और वीर हनुमान सिंह खेल पुरस्कार से भी सम्मानित हैं।

जयदीप ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता जानकी साहू, पिता कृष्णा साहू और पत्नी सोनल साहू को दिया।

वाडा की मौजूदगी से बढ़ा भरोसा

जयदीप ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान वाडा (WADA) द्वारा पदक विजेताओं का डोप टेस्ट किया गया। इससे डोप फ्री खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बढ़ा कि फेयर प्ले को निश्चित लाभ मिलता है।

आभार व्यक्त किया

जयदीप ने पावरलिफ्टिंग इंडिया के अध्यक्ष सतीश कुमार कुदरीली, जनरल सेक्रेटरी पीजे जोसफ, सीजीपीएलए के जी सुरेश, इंद्रजीत सिंह, कैलाश जैन बरमेचा और बीएसपी के खेल विभाग प्रमुख राजेंद्र प्रसाद सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया।

उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे के प्रोत्साहन और सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। जयदीप ने भरोसा जताया कि इस उपलब्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन उन्हें शासकीय नौकरी प्रदान करेगी।

बोरई हाई स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव, 7 लाख रुपये के अतिरिक्त कक्ष का हुआ भूमिपूजन

विधायक ललित चंद्राकर ने कक्षा पहली, छठवीं और नवमी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया गया स्वागत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शासकीय हाई स्कूल बोरई में बुधवार को शाला प्रवेशोत्सव एवं अतिरिक्त कक्ष के भूमिपूजन कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) ललित चंद्राकर ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कक्षा पहली, छठवीं और नवमी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाई तथा पुस्तकें और स्कूल गणवेश वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम के दौरान विधायक ने शाला परिसर में 7 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का विधि-विधान से भूमिपूजन भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चे देश और समाज का भविष्य हैं तथा प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कक्ष के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा और शाला प्रवेशोत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है।

उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही शिक्षकों और शाला विकास समिति की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण का आधार बताया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति प्रिया साहू, जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन, सरपंच ओमेश्वर यादव, मंडल अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, जिला मंत्री गिरेश साहू, शाला विकास समिति अध्यक्ष परमानंद यादव, प्राचार्य दिनेशचंद्र रक्सेल, प्रधानपाठक दिनेश ताम्रकार सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, शाला विकास समिति के सदस्य, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

खास खबर

वार्ड-50 और 53 में विकास कार्यों की सौगात, महापौर ने नागरिको के साथ किया भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों को गति देते हुए महापौर अलका बाघमार ने बुधवार को वार्ड क्रमांक 50 एवं 53 में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, वार्ड 50 पार्षद रेखा बंजारे, वार्ड 53 पार्षद सविता साहू, रंजीता पाटिल, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, ज्ञानदास बंजारे, अमितेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक उपस्थित रहे।

महापौर अलका बाघमार द्वारा वार्ड क्रमांक 50 बोरसी भाठा-पूर्व क्षेत्र में एलआईजी 154 से 142 एवं 192 से 199 तथा बंशी विहार गली नंबर-1 में डी. बरवा के घर से चौरसिया घर तक आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। उक्त निर्माण कार्य की लागत राशि 12.50 लाख रुपये है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 53 मिनाक्षी नगर स्थित शिव मंदिर के सामने महापौर निधि से स्वीकृत 5 लाख रुपये की लागत से बनने वाले मंच निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया गया। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान वाडर्वासियों ने क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं शुरुआत के लिए महापौर अलका बाघमार का आभार व्यक्त किया। महापौर ने नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। सड़क, नाली, पुलिया सहित आवश्यक विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

जिले में 11 से 18 जुलाई तक मनाया जाएगा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा

दुर्ग। जिले में कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में आगामी 11 से 18 जुलाई 2026 तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का विशेष आयोजन किया जा रहा है। "जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल" ध्येय के साथ मनाए जाने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुदाय को गभर्धारण के उचित समय, दो बच्चों के मध्य न्यूनतम 3 साल का सुरक्षित अंतराल रखने और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। अभियान के दौरान आम जनता के बीच व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और परिवार नियोजन सेवाओं की उपयोगिता बताने के लिए सभी विकासखंडों के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 'सास-बहू सम्मेलन' एवं 'मोर मितान मोर संगवारी चौपाल' जैसे जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

निधन — **बीके सराफ**

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व उप महाप्रबंधक बी.के. सराफ का बुधवार शाम को निधन हो गया। अंतिम यात्रा 10 जुलाई को उनके निवास स्थान प्लॉट नं.-9, प्रियंका नगर से सुबह 11 बजे रिसाली मुक्तिधाम के लिए निकली जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वे श्रीमती उषा सराफ के पति और पूनम सोनी, डॉ. प्रीति सोनी और आदित्य सराफ के पिता थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे।

पानी निकासी बंद होने से खेतों में जलभराव, किसानों ने कलेक्टर सिंह से लगाई गुहार

जनदर्शन में विभिन्न मांगों और समस्याओं से संबंधित 127 आवेदन प्राप्त हुए

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित 127 आवेदन प्राप्त हुए।

जनदर्शन में प्राप्त विभिन्न आवेदनों पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली और उक्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में ग्राम अंजोरा के किसानों ने खेतों में बरसाती पानी की निकासी कराने की मांग की है। किसानों ने बताया कि गांव के एक किसान द्वारा अपने खेत में ऊंची मेड़ बना देने से बरसाती पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। वर्षों से खेतों का बरसाती पानी एक-दूसरे के खेतों से होकर निकलता रहा है, लेकिन पानी की निकासी बंद होने से कई किसानों के खेतों में जलभराव हो गया है। इससे धान की फसल के खराब होने की आशंका बढ़ गई है।

किसानों को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने जनपद दुर्ग सीईओ को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। ग्राम परसाही के ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि परसाही से सिर्री मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान करीब 50 परिवारों के मकान प्रभावित हुए थे, जिनमें कई मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। ग्रामीणों ने बताया कि जनवरी 2024 में मकान टूटने के बाद से अब तक किसी भी प्रभावित परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में संबंधित विभाग को भी आवेदन दिए जा चुके हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है।

इस पर कलेक्टर ने एसडीएम पाटन को नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा। उल्लास नगर, बॉम्बे आवास और अयप्पा नगर के रहवासियों ने जाम नालियों, जलभराव और दूषित पेयजल की समस्या के संबंध में आवेदन दिया। रहवासियों ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बाद नाली पूरी तरह जाम हो गई है, जिससे गंदा पानी घरों के सामने और आसपास जमा हो रहा है। गंदे पानी के बीच से पेयजल पाइपलाइन गुजरने के कारण पानी दूषित होने की आशंका है। साथ ही क्षेत्र में दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। इस संबंध में वार्ड पार्षद और नगर निगम में इसकी शिकायत की गई थी। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई आयुक्त को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

आधार नामांकन व अपडेट कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन में लोक निर्माण विभाग के मीटिंग हॉल में जिला दुर्ग के आधार ऑपरेटरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में दुर्ग जिले के 58 तथा खैरागढ़ जिले के 4 आधार ऑपरेटरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के असिस्टेंट मैनेजर मो. सौबान मोहिदीन द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आधार नामांकन एवं आधार अद्यतन कार्यों को यूआईडीएआई के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान ऑपरेटरों को दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी अपडेट, जन्मतिथि संशोधन, जेंडर लिमिट क्रॉस, नाम लिमिट क्रॉस, पेनल्टी संबंधी प्रावधान, आधार रद्द एवं निष्क्रिय मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ऑपरेटरों द्वारा उठाए गए विभिन्न तकनीकी एवं कार्य संबंधी प्रश्नों का विस्तार से समाधान किया गया। कार्यक्रम में ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक, जिला समन्वयक एवं एमटीओ भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के माध्यम से आधार सेवाओं को और अधिक प्रभावी, सटीक एवं नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

274 वारंट तामील, दुर्ग पुलिस का विशेष अभियान जारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

फरार स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तीन दिनों में कुल 274 वारंटों का सफल निष्पादन किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 5 से 7 जुलाई 2026 तक जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान के दौरान 107 गिरफ्तारी वारंट तथा 167 स्थायी वारंट तामील किए गए।

पुलिस ने बताया कि अभियान के लिए सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों ने वारंटियों के संभावित ठिकानों, रिश्तेदारों के घरों और अन्य स्थानों पर लगातार दबिश दी। साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर तकनीकी सहायता एवं स्थानीय सूचनाओं के आधार पर फरार वारंटियों की तलाश की गई। गिरफ्तार किए गए सभी वारंटियों को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में अभियान संचालित किया गया। थाना एवं चौकी प्रभारियों को लंबित वारंटों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान में थाना एवं चौकी प्रभारियों, विवेचकों, वारंट सेल, पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा पुलिस अधिकारियों एवं कमर्चारियों ने समन्वित कार्रवाई कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दुर्ग पुलिस का कहना है कि न्यायालयीन आदेशों का प्रभावी पालन, लंबित वारंटों का शीघ्र निराकरण तथा जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी फरार वारंटी के संबंध में कोई जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार वारंटियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और कानून से बचने का हर प्रयास विफल किया जाएगा।

जिला चिकित्सालय दुर्ग के ब्लड बैंक की तत्परता से गंभीर मरीजों को मिला जीवनदायी रक्त

रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र सहित चार रक्तदाताओं ने निभाई मानवता की मिसाल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला चिकित्सालय दुर्ग के ब्लड बैंक की त्वरित पहल से गुरुवार को फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती दो गंभीर मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया गया। ब्लड बैंक स्टाफ की सक्रियता और स्वैच्छिक रक्तदाताओं के सहयोग से दोनों मरीजों के लिए आवश्यक रक्त की व्यवस्था कर उनकी मदद की गई।

फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती गंभीर मरीज सावित्री यदु को अ पॉजिटिव तथा रोशनी निषाद को अइ पॉजिटिव रक्त की तत्काल आवश्यकता थी। इस पर जिला चिकित्सालय दुर्ग के सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशीष कुमार मिंज एवं ब्लड बैंक प्रभारी अधिकारी डॉ. संतराम चुरेंद्र के मार्गदर्शन में ब्लड बैंक स्टाफ हिमांशु चंद्राकर ने रक्तदाताओं से संपर्क कर तत्काल उन्हें ब्लड बैंक बुलाया।

रक्तदान के लिए शेख जुनेद (42 वर्ष) एवं तिलक सिंह राजपूत (50 वर्ष) ने अ पॉजिटिव रक्तदान किया, जबकि राकेश (29 वर्ष) ने अइ पॉजिटिव रक्त देकर मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इसी दौरान रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई के बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र नीरज साहू (24 वर्ष) ने भी अइ पॉजिटिव रक्त का अपना तीसरा स्वैच्छिक रक्तदान किया। उन्होंने स्वीटी आदित्य मैडम की उपस्थिति में रक्तदान कर युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया।

रक्तदान के दौरान ब्लड बैंक काउंसलर टी.एस. एंथोनी, नर्सिंग ऑफिसर सती गुप्ता एवं तरूणा रावत, लैब टेक्नोलॉजिस्ट रोशन सिंह, ब्लड बैंक सुपरवाइजर रूपेश सर्पे, लैब टेक्नीशियन भूपेश दिल्लीवार, तरुण महिलांगे, अंशु नेताम तथा माला देशमुख उपस्थित रहे।

अस्पताल प्रशासन एवं ब्लड बैंक की टीम ने सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके इस मानवीय कार्य की सराहना की और कहा कि समय पर किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद के लिए नया जीवन साबित हो सकता है।

दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लॉक के जर्जर हो चुके भवनों व कमरों को किए जाएंगे डिस्मेंटल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के जर्जर हो चुके भवनों और कमरों को डिस्मेंटल (ध्वस्त) करने की अनुमति दे दी है। जिला शिक्षा अधिकारी और लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग के प्रतिवेदन और प्रस्ताव के आधार पर इन अनुपयोगी और असुरक्षित ढांचों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि वतर्मान में चिन्हित किए गए स्कूलों के अतिरिक्त, क्षेत्र के अन्य जर्जर भवनों (शेष) का भी लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर शीघ्र ही उन्हें भी डिस्मेंटल करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के तीनों प्रमुख विकासखंडों के कुल 66 शासकीय स्कूलों में यह कारर्वाई की जाएगी। जारी सूची के अनुसार, दुर्ग विकासखंड के अंतर्गत कुल 08 शासकीय स्कूलों के जर्जर कक्ष/भवन शमिल हैं। जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला तितुरडीह क्रमांक 01 के 3 कक्ष और 1 हॉल, शासकीय प्राथमिक शाला कातुलबोड़ के 5 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुपेला के 9 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सुपेला क्रमांक 01 के 10 कमरा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला वृन्दानगर के 1 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला जुनवानी के 04 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सुभाषनगर के 04 कक्ष व 1 बरामदा और शासकीय प्राथमिक शाला केम्प 01 भिलाई के पूरे भवन को डिस्मेंटल किया जाएगा ।

इसी प्रकार धमधा विकासखंड के तहत कुल 26 शासकीय स्कूलों के जर्जर कक्ष/भवन शामिल हैं। जिसके तहत शासकीय प्राथमिक शाला टेंगाभाट का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला धौराभांठा के 02 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सुरडुंग के कुल 03 कक्ष, 02 बरामदा व 1 सीढ़ी, शासकीय प्राथमिक शाला लिमतरा के 04 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला रिंगनी के 02 कक्ष व 01 बरामदा, शासकीय प्राथमिक शाला गोढ़ी के 02 कक्ष व 01 बरामदा, शासकीय प्राथमिक शाला दारगांव के 02 कक्ष व 01 हाल, शासकीय प्राथमिक शाला मोहलई का 01 कक्ष व 01 हाल, शासकीय प्राथमिक शाला मोहरेंगा के 04 कक्ष व 01 हाल, शासकीय प्राथमिक शाला मुड़पार ना. के 02 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सेमरिया गि. के 07 कक्ष व 01 हाल, शासकीय प्राथमिक शाला न. अकोला का 01 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोढ़ी के 03 कक्ष व 01 हॉल, तथा शासकीय प्राथमिक शाला पाहरा के 04 कक्ष व 01 बरामदा को ढहाया जाएगा। इसके साथ ही शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला जरवाय के 02 कक्ष व 01 बरामदा, शासकीय प्राथमिक शाला धिकुड़िया के 02 कक्ष व 01 हॉल, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेमरिया गि. के 4 कक्ष व 01 हॉल, शासकीय प्राथमिक शाला नंदौरी के 02 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला हरदी का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला पिटौरा के 02 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सांकरा के 03 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला मलपुरीखुर्द का 01 कक्ष (किचन), शासकीय प्राथमिक शाला मुरमुंदा के 02 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला अहिवारा के 05 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला खेरधा का 01 कक्ष और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेरधा के 02 कक्ष व 01 बरामदा को भी निष्प्रयोज्य मानकर डिस्मेंटल किया जा रहा है।

इसी क्रम में पाटन विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कुल 32 शासकीय स्कूलों में भी यह कारर्वाई की जा रही है, जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला सोनपुर के 02 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला खम्हरिया ड का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला गाड़ाडीह के 3 कक्ष व शौचालय, शासकीय प्राथमिक शाला बोदल (मटंग) के 4 कक्ष व शौचालय, शासकीय प्राथमिक शाला चीचा का 1 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव के 2 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला परेवाडीह का 1 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला गोंड़पेण्डी का 1 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला पहन्दा अ के 13 कक्ष व 2 बरामदा, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला पाटन के 04 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जमराव का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला मजार चौक सेलूद का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला धूमा के 04 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला शुक्लाडीह का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला डीह का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला दरबारमोखली के 04 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला देमार नवागांव का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला लोहरसी वरि. के 02 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला भांठागांव का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला बालक जामगांव एम के 02 कक्ष तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झीट का 01 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सांकरा का 01 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला असोगा का 01 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तुलसी का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला बजरंगपारा अमलेश्वर का 01 कक्ष, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेलूद का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सिपकोना के 03 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सेजस रानीतराई का 01 कक्ष, शासकीय प्राथमिक शाला सेलूद का 01 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मर्रा के 02 कक्ष, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केसरा का 01 कक्ष और शासकीय प्राथमिक शाला भनसुली के का 01 कक्ष डिस्मेंटल किया जाएगा।

सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है–मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

आरंग विधानसभा के विकास को मिली नई गति, 128 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री साय समोदा में लोकार्पण–भूमिपूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आरंग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में आयोजित कार्यक्रम में 128 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम पंचायत रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉप डैम निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा के पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण तथा ग्राम तुलसी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि "मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी" केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की कार्यशैली और जनविश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 10 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है तथा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 28 किश्तों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही आधारित प्रशासन स्थापित करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज एवं कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु के माध्यम से 520 से अधिक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सहकारिता, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। उन्होंने नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। पात्र उपभोक्ता "मोर बिजली" मोबाइल एप अथवा वेबसाइट के माध्यम से सितंबर तक पंजीयन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कार्यक्रम में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आरंग विधानसभा क्षेत्र को अब तक 858 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और सुशासन की नई दिशा स्थापित हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के अंतर्गत आंवला का पौधारोपण किया। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की तथा जिला प्रशासन के मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा, छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खास खबर

उप मुख्यमंत्री साव ने "जोहार श्री जगन्नाथ रथ" को झंडा दिखाकर किया रवाना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं और प्रार्थनाओं को जगन्नाथ धाम तक पहुंचाएगी रथ

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय से "जोहार श्री जगन्नाथ रथ" को झंडा दिखाकर रवाना किया। विधायक दीपेश साहू भी इस दौरान मौजूद थे। माय एफएम 94.3 और एटी ज्वेलर्स द्वारा तैयार यह रथ प्रदेश के श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं और प्रार्थनाओं को जगन्नाथ धाम तक पहुंचाएगी। श्रद्धालु अपनी मनोकामना व प्रार्थना लिखकर इस रथ के कलश में समर्पित कर सकेंगे, जिसे 94.3 माय एफएम की टीम श्री जगन्नाथ धाम तक लेकर जाएगी। यह अभिनव पहल भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और मनोकामनाओं को उनके पावन धाम तक पहुँचाने का सुंदर माध्यम बनेगी।

वन्यजीवों के शिकार पर बड़ी कार्रवाई, धामन सांप और गोह के शिकार के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन में वन्यजीवों के शिकार के मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

धामन सांप और गोह के शिकार का मामला : वनमंडलाधिकारी कांकेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 4 जुलाई को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) के पांच लोगों पर तीन धामन (असोड़िया) सांप और एक गोह का शिकार करने का आरोप है। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को एक आरोपी के घर ले जाकर उनके टुकड़े किए गए और भोजन के रूप में उपयोग किया गया। मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी जाधव श्रीकृष्ण के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता तथा एंटी–पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वन विभाग ने दी सख्त चेतावनी : वन विभाग ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित वन्यजीवों के शिकार, अवैध कब्जे या व्यापार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करें तथा शिकार या वन्यजीव अपराध से संबंधित किसी भी सूचना की तत्काल विभाग को जानकारी दें। वन्यजीवों की सुरक्षा जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सरकार गठन के बाद 11 लाख से अधिक पीएम आवास पूर्ण, सीएम ने दी नए आवास की चाबी

मोर गांव–मोर पानी महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित कॉम्पेंडियम का किया विमोचन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में सरकार गठन के बाद 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने तथा मोर गांव–मोर पानी महाअभियान की उल्लेखनीय उपलब्धियों से संबंधित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 11 लाख आवास पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 हितग्राहियों को उनके नए आवास की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान कर सम्मानित किया तथा मोर गांव मोर पानी महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित कॉम्पेंडियम का विमोचन किया।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गठन के तुरंत बाद अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राशि जारी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें से विगत वित्तीय वर्ष में लगभग 6 लाख आवास पूर्ण किए गए, जो एक वर्ष में देश में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने की उपलब्धि है। वहीं वतर्मान वित्तीय वर्ष के प्रथम 100 दिनों (1 अप्रैल से 9 जुलाई) में ही 1 लाख 51 हजार आवास पूर्ण किए गए हैं। अर्थात प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,500 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में मोर गांव–मोर पानी महाअभियान के उत्कृष्ट कायी पर एक पुस्तिका विमोचित की गई। उल्लेखनीय है कि यह महाअभियान 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। जनभागीदारी आधारित इस अभियान के अंतर्गत पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा एवं वर्तमान वीबी– जीरामजी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य स्वीकृत एवं क्रियान्वित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत आजीविका डबरी, नवा तरिया, कंटूर ट्रेंच सहित विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संरक्षण, भूजल संवर्धन एवं ग्रामीण आजीविका को नई दिशा दी जा रही है।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कमर्कार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076
शिकायतों का हो रहा त्वरित समाधान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इस दिशा में एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुई है, जहां दर्ज शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

जांजगीर–चांपा जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे स्वयं हितग्राहियों से दूरभाष पर संपर्क कर फीडबैक ले रहे हैं। वे शिकायतों के निराकरण के संबंध में नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी संतुष्टि की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि प्रत्येक शिकायत का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि स्थायी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

इसी क्रम में पामगढ़ विकासखंड के ग्राम भंवतरा निवासी देवेन्द्र दिनकर ने राशन कार्ड एवं राशन आबंटन से संबंधित समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी शिकायत का निराकरण किया गया। इसके बाद कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने स्वयं दूरभाष पर उनसे चर्चा कर समाधान की जानकारी ली। श्री दिनकर ने समस्या के त्वरित समाधान पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।

इसी प्रकार पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंडरी निवासी नवीन कुमार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन के संकल्प को मिल रही मजबूती

वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त जारी किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी समस्या का समाधान किया गया। कलेक्टर ने स्वयं उनसे दूरभाष पर चर्चा कर फीडबैक प्राप्त किया। श्री वर्मा ने त्वरित कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की।

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय–सीमा में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंच सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिक–केंद्रित प्रशासन को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन और शासन के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम बनकर लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सुशासन की भावना को और अधिक मजबूत कर रही है।

मुंगेली पुलिस को मिले 68 मोबाइल डाटा टर्मिनल, घटनास्थल से ही होगी ऑनलाइन विवेचना

एसपी भोजराम पटेल ने थाना–चौकी प्रभारियों को किया उपकरणों का वितरण, नए कानूनों के तहत विवेचना होगी तकनीकी, पारदर्शी और समयबद्ध

नई दृष्टिबिंदु / मुंगेली

नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप विवेचना को तकनीकी और पारदर्शी बनाने के लिए मुंगेली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बुधवार को जिले के थाना–चौकी प्रभारियों और विवेचकों को 68 मोबाइल डाटा टर्मिनल डिवाइस वितरित किए। इस अवसर पर जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना–चौकी प्रभारी और विवेचक उपस्थित रहे।

घटनास्थल से ही ऑनलाइन विवेचना

इन डिवाइस के मिलने से अब विवेचक घटनास्थल से ही जांच की कार्रवाई कर सकेंगे। घटनास्थल के फोटो, वीडियो, डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज तत्काल ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे।

इससे विवेचना में होने वाले अनावश्यक विलंब में कमी आएगी और वरिष्ठ अधिकारी प्रकरणों की निगरानी भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि यह पहल मुंगेली पुलिस को डिजिटल पुलिसिंग में मजबूत करेगी। नई तकनीक के उपयोग से जांच अधिक तेज, सटीक और गुणवत्तापूर्ण होगी, जिससे आम जनता को त्वरित और बेहतर पुलिस सेवा मिल सकेगी।

थानों को इस तरह मिले डिवाइस

वितरित किए गए 68 MDT डिवाइस में से
- थाना सिटी कोतवाली मुंगेली और लोरमी को 10–10
- सरगांव को 7
- पथरिया, लालपुर, जरहागांव, बिल्फी को 6–6
- फास्टरपुर को 5
- चौकी डिण्डौरी को 4, खुड़िया को 3, साकेत को 2
- अजाक थाना को 2 और साइबर सेल को 1 डिवाइस दिए गए।

लोनिवि राज्य का 'ग्रोथ इंजन', विभाग पर अधोसंरचना विकसित करने की अहम जिम्मेदारी –अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा, निर्माण कार्यों की गहन मॉनिटरिंग और निरीक्षण के दिए निर्देश, ठेकेदारों से बेहतर समन्वय कर कार्यों में तेजी लाने कहा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय निर्माण भवन में प्रदेशभर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक कार्यों की प्रगति पर बारीक नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड पर जाकर निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद रख कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता और क्षमता फील्ड पर दिखनी चाहिए। उन्होंने प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यों के लिए समयानुकूल नई कार्यप्रणाली और कार्य संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तत्परता से पूर्ण कर आगामी सितम्बर–अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि बरसात के तत्काल बाद पूरी गति से काम शुरू हो सके। उन्होंने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूर्ण कर समय पर काम प्रारंभ कराने को कहा।

बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य का 'ग्रोथ इंजन' है। राज्य में सड़क, पुल–पुलिया और भवन निर्माण के साथ ही सभी तरह की अधोसंरचना विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विभाग को भी अहम भूमिका निभाना है। उन्होंने इसके लिए पूरी सक्रियता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को काम का पुराना ढर्रा बदलने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के समय पर बिल तैयार करने और उनका हर महीने भुगतान करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड पर विभाग के काम और उनके परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने सड़कों और पुल–पुलियों सहित स्कूलों, कॉलेजों, ऑडिटोरियम, कार्यालयों, आवासगृहों एवं अन्य

भवनों के निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के साथ अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन्स के अनुसार प्रगति सुनिश्चित कर समय–सीमा में काम पूरा कराने को कहा। उन्होंने सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को भू–अर्जन के कार्यों में तेजी लाने इससे संबंधित कानूनों व नियमों की व्यापक एवं समग्र जानकारी के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों तथा उप अभियंताओं की कायर्शाला आयोजित करने के निर्देश दिए।

श्री साव ने पहुंचविहीन गांवों तक साल भर कनेक्टीविटी बनाए रखने के लिए सड़कों और पुलों के प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राथमिकता से तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुराने लंबित कार्यों से जुड़ी समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर काम आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों को ब्लैक–लिस्ट करने और उनके अनुबंध टर्मिनेट करने की कार्यवाही के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा अनुशंसित कार्यों के साथ ही द्रुतगामी सड़कों व पुलों, पहुंचविहीन गांवों के लिए पक्की सड़कों, जिले की जरूरतों और विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों की प्राथमिकता तय कर आगामी 31 अगस्त तक नए कार्यों के प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के काम पूरा होने के बाद तत्काल इन्हें संबंधित विभागों या नगरीय निकायों को हैंडओवर करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव एसएन श्रीवास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंता और सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता भी बैठक में मौजूद थे।

संपादकीय

राहुल गांधी गुटबाजी नहीं चाहते और वही होती रहती है

आम तौर पर माना जाता है कि पार्टी है तो नेता है ध्यह सच भी है कि पार्टी होने के कारण ही सब नेता व कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस में इस सच को नहीं माना जाता है,वहां माना जाता है कि हमारा नेता है इसलिए पार्टी है। पार्टी होने के कारण हमारा नेता नहीं है। यानी पार्टी हमारे नेता से बड़ी नहीं हो सकती, हमारा नेता पार्टी से बड़ा रहा है और आगे भी पार्टी से बड़ा रहेगा।कांग्रेस के बड़े और आलाकमान के प्रति वफादार नेता यही कहते रहते हैं और दूसरे नेताओं से यही मानने को कहते हैं। पंजाब कांग्रेस में बगावत से स्वर सुनाई दे रहे है तो वहां के प्रभारी और छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल जब यह कहते हैं कि पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व में बदलाव बच्चों का खेल नहीं है तो वह इसी सत्य की ओर ही इशारा करते हैं कि जब आलाकमान ने कोई फैसला ले लिया तो वह अंतिम होता है उसे बदला नहीं जा सकता। यानी सबको आलाकमान की बात माननी होगी।आलाकमान देश में?? नहीं है इसलिए दिल्ली से पंजाब नेताओं को भेजा जा रहा है कि विवाद को खत्म कराया जाए,भूपेश बघेल भी इसी कोशिश में लगे है कि पंजाब के नेता उसे मान लें जो आलाकमान ने कह दिया है।

राहुल गांधी देश में नहीं है,पंजाब में कांग्रेस गुटबाजी सतह पर है और पूरे देश में चर्चा की विषय बनी हुई है। जिस राज्य में भी चुनाव होना होता है तो वहां चुनाव के पहले गुटबाजी सतह पर जरूर आती है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव के पहले जितने गुट के नेता होते है,वह चाहते हैं कि सीएम का चेहरा उनको बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस में अक्सर होता यह है कि प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है,वही बाद में सीएम बनाया जाता है इसलिए चुनाव के पहले कांग्रेस के बड़े नेता जो सीएम पद के दावेदार होते हैं वह चाहते हैं कि उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि सीएम पद पर उनकी स्वाभाविक दावेदारी रहे। वह कह सकें कि मैंने कांग्रेस को चुनाव जिताया है इसलिए सीएम तो मुझे ही बनाया जाना चाहिए।पंजाब के पूर्व सीएम व सांसद चरणजीत सिंह चन्नी चाहते थे कि आलाकमान उनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए।कांग्रेस आलाकमान को भी पता था यह हो सकता है इसलिए उसने पहले तो कई कुछ लोगों को भेजा कि पंजाब में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, कौन कांग्रेस को चुनाव जिता सकता है। कई नेताओं ने पंजाब जाकर सभी छोड़े बड़े नेताओं से मिलकर एक रिपोर्ट बनाई।

कांग्रेस नेताओं ने वह रिपोर्ट आलाकमान को दी । इस रिपोर्ट के अनुसार तो पूर्व सीएम चन्नी सबसे लोकप्रिय नेता थे, इस बात का पता चन्नी को था कि रिपोर्ट तो उनके पक्ष में है और आलाकमान रिपोर्ट के अ?ुसार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान जैसा चन्नी चाहते थे, वैसा नहीं किया। उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा वारिंग उनको अध्यक्ष बनाए रखा और चन्नी को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। चन्नी समथर्को को आलाकमान का यह फैसला पसंद नहीं आया, उनकी मांग है कि आलाकमान अपने फैसले पर फिर से विचार करे और चन्नी को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए ।इसी बात पर भूपेश बघेल ने कहा है कि पंजाब में नेतृत्व का बदलाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने मांग की और मांग मान ली जाएगी। चन्नी समथर्कों की नाराजगी इस बात से है कि आलाकमान को जब प्रदेश अध्यक्ष बदलना नहीं था तो उसने कांग्रेस नेताओं को यह जानने पंजाब भेजा क्यों कि वहां सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। जब यह पता लग गया तो चन्नी को अध्यक्ष बनाया क्यों नहीं गया।

कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की गलती की थी और उस गलती के कारण कांग्रेस जो चुनाव जीत रही थी,चुनाव हार गई थी। कांग्रेस आलाकमान गलती करता है और उसका खामियाजा कांग्रेस और कांग्रेस नेताओ को राज्य में भुगतना पड़ता है। चन्नी को अमरिदंर सिंह के मुकाबले किसने खड़ा किया था,आलाकमान ने। आज वही चन्नी आलाकमान के फैसले को मानने से मना कर रहा है ।चन्नी और समर्थक अड़े हुए है कि चन्नी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए ।सभी सक्रिय है विवाद को सुलझाने के लिए लेकिन विवाद सुलझा नहीं है, भूपेश पंजाब गए तो चन्नी उनसे मिलने नहीं आए और सोशल मीडिया मे उनकी तरफ से तस्वीर डाली गई है जिसमें लिखा गया है कि एकता में बल है। यानी हम सब एकजुट है। आलाकमान चाहता है चुनाव के पहले कांग्रेस एकजुट दिखे लेकिन गुटबाजी के चलते कई राज्यो में कांग्रेस एकजुट दिखती नही है। कांग्रेस आलाकमान कहता है कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस में गुटबाजी चुनाव के समय सबसे ज्यादा होती है ।इसी का नुकसान कांग्रेस को कई राज्यों में हुआ है।

केरल चुनाव में कांग्रेस के जीतने के बाद भी गुटबाजी जमकर हुई थी, राज्य के कांग्रेस नेता चाहते थे कि सतीशन को सीएम बनाया जाए और आलाकमान चाहता था कि वेणुगोपाल को सीएम बने ।दस दिन बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य में आलाकमान की पसंद का सीएम नहीं बना और पहली बार कांग्रेस नेताओं को इस सच का पता चला कि राज्य में उनकी पकड़ मजबूत है तो आलाकमान को झुकाया जा सकता है,उससे अपनी बात मनवाई जा सकती है ।कर्नाटक फैसले से भी आलाकमान कमजोर हुआ है क्योंकि डीके शिवकुमार को सीएम बनाना पड़ा ।जबकि छत्तीसगढ़ व राजस्थान में जो सीएम बना वह पांच साल तक सीएम बना रहा था। दोनों जगह कांग्रेस चुनाव हारी। कर्नाटक में कांग्रेस ने हारे इसलिए सीएम बदला गया है लेकिन गुटबाजी के चलते जो हाल हरियाणा में कांग्रेस का हुआ, वही हाल पंजाब,कर्नाटक में होने के पूरे आसार है।

हिंद-प्रशांत में भारत का बढ़ता सामर्थ्य और साझेदारियां

ललित गर्ग

भारत आज केवल विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने जिस आत्मविश्वास, स्पष्टता और दूरदृष्टि का परिचय दिया है, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। कभी जो भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भर था, वही भारत आज आधुनिक मिसाइलों, रक्षा प्रणालियों और सैन्य उपकरणों का निर्यात करने वाला विश्वसनीय राष्ट्र बन चुका है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक, वैज्ञानिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का भी प्रमाण है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ताएं इस नई विदेश नीति की सफलता का सशक्त उदाहरण हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में हुए समझौते यह स्पष्ट करते हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल रही है। ह्यमेक इन इंडियाह्न और ह्यआत्मनिर्भर भारतह्न अभियान ने रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका रॉकेट सिस्टम, तेजस लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज विश्व के अनेक देशों का विश्वास जीत रहे हैं। भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल आज केवल भारतीय सेना की शक्ति का प्रतीक

नहीं हैं, बल्कि विश्व के अनेक देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बन रही हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन हथियारों की प्रभावशीलता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। यही कारण है कि इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश अपने सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए अस्त्र मिसाइल प्राप्त करना चाहते हैं तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत के रक्षा उद्योग के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है।

इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। मलक्का जलडमरूमध्य जैसे विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर उसकी रणनीतिक स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग केवल दो देशों के संबंधों को मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी नया आयाम देता है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत अब किसी पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि समान साझेदारी और परस्पर सम्मान के आधार पर संबंध स्थापित कर रहा है। भारत किसी देश पर अपनी शक्ति थोपने में विश्वास नहीं रखता। उसकी विदेश नीति का मूल मंत्र है-ह्यवसुधैव कुटुम्बकम्ह्न, ह्यसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासह्न और ह्यविश्व बंधुत्वह्न। यही कारण है कि भारत जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भी विश्वासपूर्ण साझेदारी विकसित कर रहा है।

आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है। चीन का विस्तारवादी रवैया, दक्षिण चीन सागर में उसका सैन्यीकरण, छोटे देशों पर दबाव बनाने की नीति तथा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत ने इन परिस्थितियों में संतुलित, शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ रणनीति अपनाई है। भारत किसी के विरुद्ध युद्ध नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से कोई समझौता भी नहीं करता। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत को विश्व का विश्वसनीय साझेदार बनाता है। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए स्पष्ट संदेश है कि नया भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत अब केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीकी युद्ध की तैयारियों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन इस दिशा में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उन्होंने भारत की वैश्विक छवि को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र भारत को केवल विशाल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय मित्र, तकनीकी साझेदार, निवेश गंतव्य और सुरक्षा सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। जी-20 की सफल अध्यक्षता, क्वाड की सक्रिय भूमिका, इंडो-पैसिफिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की आवाज तथा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व इसकी पुष्टि करता है। भारत की विदेश नीति अब केवल कूटनीतिक दस्तावेज नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बन चुकी है। रक्षा निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है, लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति मिल रही है और भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत हो रहे हैं। यह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र सदैव शांति, सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान रहा है। आदर्श स्थिति में किसी भी दो देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव किसी तीसरे देश के प्रति वैमनस्य या शत्रुता पर नहीं, बल्कि साझा विकास, सुरक्षा और स्थिरता पर आधारित होनी चाहिए। किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति-संतुलन से संचालित होती है। आज चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य एवं आर्थिक गठजोड़ को सऊदी अरब तक विस्तार देने के प्रयासों में जुटे हैं। हाल के सप्ताहों में सऊदी नेतृत्व और बीजिंग के बीच बढ़ती सक्रियता इस बदलते भू-राजनीतिक समीकरण का संकेत है। यद्यपि सऊदी अरब की प्राथमिक सुरक्षा चिंताएं पाकिस्तान और चीन से अलग हैं तथा उसका प्रमुख ध्यान खाड़ी क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव पर केंद्रित है, फिर भी बदलते वैश्विक समीकरण भारत के लिए सतर्क रहने का संदेश देते हैं। पाकिस्तान हर परिस्थिति में भारत के विरुद्ध रणनीतिक लाभ उठाने का अवसर तलाशता है, जबकि चीन अपने विस्तारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी, संतुलित और सक्रिय विदेश नीति भारत के हितों की प्रभावी सुरक्षा करती दिखाई देती है। उनकी कूटनीति केवल मित्र देशों के साथ विश्वास बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की शरारतों, षड्यंत्रों तथा सामरिक चुनौतियों का संयमित और दृढ़ता से सामना करने की क्षमता भी प्रदर्शित करती है। यही दूरगामी सोच भारत को एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

आज विश्व एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो शक्ति और शांति, विकास और सुरक्षा, तकनीक और मानवता के बीच संतुलन स्थापित कर सके। भारत इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह सिद्ध किया है कि सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम होने के साथ-साथ विश्व शांति और मानव कल्याण का भी वाहक बने। निस्संदेह भारत अब विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का प्रतीक है। वह हथियारों का निर्माण युद्ध भड़काने के लिए नहीं, बल्कि शांति की रक्षा और संतुलन स्थापित करने के लिए कर रहा है। यही भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व की पहचान है। आने वाले वर्षों में भारत की यही संतुलित विदेश नीति, आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति और विश्वसनीय कूटनीतिक नेतृत्व न केवल विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगा, बल्कि विश्व व्यवस्था को भी अधिक सुरक्षित, संतुलित और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करेगा।

अल नीनो का बढ़ता प्रकोप और उसका वैश्विक प्रभाव

महेन्द्र तिवारी

प्रकृति के चक्र में महासागरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे न केवल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं बल्कि वैश्विक मौसम प्रणालियों को भी संचालित करते हैं। हाल के वर्षों में प्रशांत महासागर के गर्भ में हो रहे एक बड़े बदलाव ने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की चिंताओं को गहरा कर दिया है। इस बदलाव को विज्ञान की भाषा में अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो कोई सामान्य मौसमी घटना नहीं है बल्कि यह एक अत्यंत जटिल महासागरीय और वायुमंडलीय प्रक्रिया है जो हर कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर तबाही का कारण बनती है। वर्तमान समय में चिंता की बात यह है कि वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण अल नीनो के इस बार के सारे पुराने रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आने वाले समय में दुनिया को पहले से कहीं अधिक चरम मौसम, विनाशकारी बाढ़, भीषण सूखे और अप्रत्याशित दावानल का सामना करना पड़ सकता है।

इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से समझने के लिए हमें भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सामान्य स्थिति और वायुमंडलीय चक्र को समझना होगा। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिण अमेरिका से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मजबूत व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ये हवाएं समुद्र की सतह के गर्म पानी को अपने साथ बहाकर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर ले जाती हैं। इस वजह से इंडोनेशिया और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में भारी मात्रा में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है। गर्म पानी के इस जमाव के कारण वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक मजबूत निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाती है। हवा के ऊपर उठने से घने बादलों का निर्माण होता है जिससे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया के देशों में अच्छी वर्षा होती है। यही निम्न वायुदाब क्षेत्र आगे चलकर हिंद महासागर से नमी युक्त मानसूनी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करता है जिससे भारत में एक समृद्ध मानसून का आगमन होता है। इसके विपरीत, दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों के तटों पर समुद्र की गहराई से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है जो वहाँ के मत्स्य उद्योग और सामान्य जलवायु को संतुलित रखता है। इस पूरे वायुमंडलीय चक्र को मौसम विज्ञान में वॉकर सर्कुलेशन या वॉकर चक्र कहा जाता है। परंतु अल नीनो के आगमन के साथ ही यह पूरा स्थापित चक्र पूरी तरह से उलट जाता है। अल नीनो की शुरुआत तब होती है जब प्रशांत महासागर में बहने वाली ये व्यापारिक हवाएं अप्रत्याशित रूप से कमजोर पड़ जाती हैं। हवाओं के कमजोर होने से वह शक्ति समाप्त हो जाती है जो गर्म पानी को पश्चिमी हिस्से में रोके रखती थी। परिणामस्वरूप, पश्चिमी प्रशांत महासागर में संचित विशाल गर्म जलराशि वापस पूर्व की ओर यानी दक्षिण अमेरिका के तटों की तरफ खिसकने लगती है। इसके कारण मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है। समुद्र के गर्म होने का यह क्षेत्र इतना विशाल होता है कि यह पूरे वैश्विक वायुमंडल को प्रभावित करने लगता है। जैसे ही गर्म पानी का यह क्षेत्र पूर्व की ओर खिसकता है, वैसे ही बादलों को बनाने वाला और हवा को ऊपर उठाने वाला निम्न वायुदाब का केंद्र भी इंडोनेशिया से हटकर हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के मध्य में चला जाता है।

इस दबाव प्रणाली के बदलने का सबसे बड़ा आघात भारत और उसके पड़ोसी देशों के मानसून पर पड़ता है। जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र प्रशांत महासागर के बीच में चला जाता है, तो हिंद महासागर और इंडोनेशिया के ऊपर एक विशाल उच्च वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। मौसम विज्ञान के नियमों के अनुसार उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में हवाएं ऊपर उठकर बादल बनाने के बजाय भारी होकर नीचे की ओर बैठने लगती हैं। जब हवा नीचे बैठती है तो वह बादलों के बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से दबा देती है। इस वायुमंडलीय व्यवधान के कारण जो मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से भारी नमी लेकर भारत की ओर बढ़ने वाली होती हैं, वे अपनी दिशा और ऊर्जा दोनों खो देती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाला हवाओं का यह प्रवाह कमजोर पड़ जाता है जिसके कारण मानसूनी बारिश में भारी गिरावट आती है। इतिहास गवाह है कि जब भी प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली अल नीनो सक्रिय हुआ है, तब भारत को गंभीर सूखे और मानसूनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। अल नीनो का यह प्रभाव केवल दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि इसका वैश्विक दायरा बेहद विनाशकारी होता है। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बारिश न होने से नदियां और जलाशय सूख जाते हैं, कृषि ठप हो जाती है और जंगलों में भीषण आग लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश होती है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक भयानक बाढ़ और भूस्खलन आते हैं जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। इसके अलावा समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गहरा संकट मंडराने लगता है। पेरू के तट पर ठंडे पानी का ऊपर आना बंद हो जाता है जिससे मछलियों का भोजन समाप्त हो जाता है और बड़े पैमाने पर समुद्री जीवों की मृत्यु होती है। साथ ही दुनिया भर की मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ समुद्र की इस अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पातीं और उनका बड़े पैमाने पर क्षरण होने लगता है जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। मूंगा चट्टानों का नष्ट होना पूरे समुद्री जीवन की खाद्य श्रृंखला को संकट में डाल देता है।

कविता का कोना

हिंसक होता देश हमारा

मानवता अब कहाँ खो गई ?
लिखते रहिये सच्ची बाते , सच्चाई
भी आज रो गई
कहाँ गई वो कलम हमारी , बीज
प्रेम का जो बोती थी,
कहाँ गई वो सोनी पीढ़ी , सुख दुख
की साथी होती थी ?
आज अगर खामोश रहे तो ,
बालक हमको क्या बोलेंगे ?
मक्कारी जो करते रहते , उन पर
हल्ला कब बोलेंगे ?
अभी क्रूरता नाच रही है, हिंसक
होता देश हमारा
बंद करो अब ऐसी करनी, और
बचाओ देश हमारा

अभी क्रूरता नाच रही है हिंसक
होता देश हमारा
बंद करो अब ऐसी करनी और
बचाओ देश हमारा
दुख के बादल मंडराये है , सुख
की सरिता सूख गई है,
दंड दोषियों को जल्दी दो , मातायें
अब बिलख गई है
आज बेटियां बिगड़ गई हैं ,
जिनका यश भारत गाता था,
न्याय सभी को मिलना चहिये ,
जिनका बेटा मारा जाता
न्याय नहीं अब बिकना चहिये ,
संविधान को मान दिलाओ, नस्लें
सुधरें भारत माँ की ,आज कलम
की शान बढ़ाओ
कुछ तो जहर घोलते भूपर , कई
मुखौटे लगा लिये हैं,
आडम्बर करते रहते है , झंडे
नकली बना लिये है
गंगा - जमुनी देश हमारा ,

छत्तीसगढ़ रत्न

डॉ. शिरोमणि माथुर

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का इथेनॉल पथ : उम्मीदों की उड़ान और व्यावहारिक अवरोध

अशोक भाटिया

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जुझारूपन ने फरवरी से दुनिया को ऊर्जा संकट में डाल दिया है, और मोदी सरकार की कारों में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाने की आवश्यकता का कुछ लोगों द्वारा उपहास किया गया है क्योंकि दूध में पानी की मात्रा बढ़ाने से दूध की मांग कम हो जाएगी। लेकिन सरकार की इस सोच में कुछ भी गलत नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल के इस्तेमाल को कम करने के प्रयोग पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए यह सही है कि भारत में इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जो तेल आयात पर निर्भर है ।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक प्राथमिकताओं के एक अभूतपूर्व चौराहे पर खड़ा है ऐसे समय देश ने हाल ही में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (ई20) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर दुनिया के सामने नीतिगत इच्छाशक्ति का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। वर्ष 2013-14 में जहां इथेनॉल मिश्रण की दर महज 1.5 प्रतिशत के आसपास सिमटी हुई थी, वहीं 2025-26 के कालखंड में इसका देशव्यापी स्तर पर 20 प्रतिशत तक पहुंच जाना भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की एक युगांतकारी घटना है? इस नीतिगत उछाल का प्राथमिक श्रेय केंद्र की मोदी सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को जाता है, जिसने भारत को जीवाश्म ईंधनों की विदेशी निर्भरता से मुक्त कराने और पंचामृत के तहत वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लिया है।

परंतु, इस बड़ी नीतिगत सफलता के साथ ही धरातल पर कुछ ऐसे बुनियादी सवाल और व्यावहारिक चुनौतियां भी सिर उठाने लगी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना इस दीर्घकालिक अभियान को कमजोर कर सकता है। हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्तर पर E20 ईंधन के अनिवार्य प्रसार के बाद से आम उपभोक्ताओं, मोटर वाहन उद्योग और कृषि-अथर्शास्त्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत का अचूक हथियार मानती है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक माइलेज में गिरावट और पुराने वाहनों के इंजनों की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में यह नीतिगत समीक्षा का सही समय है कि क्या भारत अपनी हरित ऊर्जा की रफ्तार को बनाए रखते हुए आम जनता की चिंताओं को वैज्ञानिक और आर्थिक धरातल पर संतुष्ट कर पा रहा है?

इस नीति की आवश्यकता को समझने के लिए सबसे पहले भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता के आंकड़ों को देखना होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 88.5 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वैश्विक राजनीति में होने वाले उतार-चढ़ाव, खाड़ी देशों के तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भारत के घरेलू बाजार और बजटीय संतुलन को सीधे प्रभावित करती है। सरकार की इस इथेनॉल नीति ने देश की मैक्रो-इकोनॉमी को एक बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। 2014-15 से लेकर मई 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश ने 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की है और करोड़ों मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को घरेलू जैव-ईंधन से प्रतिस्थापित किया है।

इस आर्थिक चक्र का दूसरा सबसे खूबसूरत पहलू इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ाव है। जैव-ईंधन का उत्पादन केवल फैक्टरियों की चहारदीवारी में नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के खेतों से शुरू होता है। गन्ने के उप-उत्पाद (शीरा), मक्का, और टूटे हुए चावल (सरप्लस अनाज) से इथेनॉल बनाने की अनुमति देकर सरकार ने किसानों को केवल अन्नदाता से ऊर्जादाता के रूप में परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया है। इस खरीद प्रक्रिया के माध्यम से किसानों और घरेलू डिस्टिलरीज को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और चीनी मिलों के गन्ना बकाया संकट पर काफी हद तक लगाम लगी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो ए20 मिश्रण ने देश के वायुमंडल को लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बचाया है, जो महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी राहत है।

नीतिगत स्तर पर जितनी यह योजना आकर्षक और देशहित में दिखाई देती है, उपभोक्ता स्तर पर इसके अनुभव उतने ही मिश्रित रहे हैं। देश के करोड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों द्वारा लगातार यह शिकायत की जा रही है कि ए20 पेट्रोल के उपयोग के बाद से वाहनों के माइलेज

में 6 से 7 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात सही भी है; इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग एक तिहाई कम होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि समान दूरी तय करने के लिए इंजन को अधिक ईंधन की खपत करनी पड़ती है। आज के इस महंगाई के दौर में, जब पेट्रोल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं, आम नागरिक को कम माइलेज के रूप में अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ महसूस हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी मोर्चे पर सबसे बड़ी चिंता मटेरियल डिग्रेडेशन यानी वाहनों के पुर्जों के खराब होने की है। इथेनॉल स्वभाव से हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका मतलब है कि यह हवा से नमी और पानी को बहुत तेजी से सोखता है। यह रासायनिक गुण पुराने वाहनों (जो विशेष रूप से ए20 के अनुकूल नहीं बने हैं) के ईंधन टैंक, पाइपलाइन और काबीरेटर या इंजेक्टर प्रणालियों में जंग और प्लास्टिक या रबर के पुर्जों के गलने का कारण बन सकता है। यद्यपि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और प्रमुख वाहन निर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प ने सेवा डेटा का हवाला देते हुए दावा किया है कि ए20 से पुराने इंजनों को कोई बड़ा या गंभीर नुकसान नहीं देखा गया है, फिर भी आम जनता के भीतर बैठा अविश्वास और डर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

जनता के इसी जमीनी विरोध और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की अपूर्ण तैयारी को देखते हुए मोदी सरकार ने हाल ही में बेहद परिपक्वता और वैज्ञानिक संयम का परिचय दिया है। पहले बाजार में ऐसी अटकलें जोरों पर थीं कि सरकार ई20 की तत्काल सफलता के बाद तेजी से 25 प्रतिशत सम्मिश्रण (ई25) की ओर बढ़ेगी। परंतु, उपभोक्ताओं के फीडबैक और वाहनों की तकनीकी सीमाओं को स्वीकार करते हुए पेट्रोलियम और परिवहन मंत्रालयों ने स्पष्ट कर दिया है कि ए25 को लागू करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सरकार ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि वर्तमान में ए20 ईंधन पूरी तरह से सुरक्षित है और उच्च मिश्रणों की तरफ कदम केवल व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों, ऑटोमोबाइल उद्योग की तैयारियों और उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही बढ़ाया जाएगा।

सरकार की इस ग्रेडेड अप्रोच की सराहना की जानी चाहिए। किसी भी देशव्यापी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश के अंतिम नागरिक के हितों के साथ कितनी सहजता से मेल खाती है। यदि सरकार बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के जबरन उच्च मिश्रण थोपती, तो इससे न केवल वाहन बाजार में व्यवधान उत्पन्न होता, बल्कि हरित ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रति जनता में एक स्थायी आक्रोश और अविश्वास पैदा हो सकता था। इस लेख में एक और गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, जो नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वह है—अन्न बनाम ईंधन का द्वंद्व। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में खाद्य सुरक्षा हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जब हम इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के जूस, मक्का और विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मिलने वाले चावल का अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं, तो इसका सीधा असर देश के खाद्य बाजार पर पड़ता है।

विगत वर्षों में चीनी के घरेलू दामों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार को कई बार इथेनॉल उत्पादन पर अस्थायी प्रतिबंध या सीमाएं लगानी पड़ी थीं, हालांकि बाद में आपूर्ति सामान्य होने पर इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। यदि किसान अनाज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा केवल ऊर्जा क्षेत्र की व्यावसायिक डिस्टिलरीज को बेचने लगेंगे, तो देश में पशुओं के चारे (जैसे मक्के से बनने वाले फीड) और आम जनता के उपभोग वाले खाद्यान्न की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए, नीति की निरंतरता के लिए कृषि भूमि के उपयोग और फसलों के चक्र का सटीक वैज्ञानिक मानचित्रण अनिवार्य है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत के उज्ज्वल और स्वच्छ भविष्य के लिए एक गैर-परक्राम्य आवश्यकता है, लेकिन इसकी सफलता का रास्ता आम जनता की जेब और भरोसे से होकर ही गुजरता है। इस नीति को बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तीन रणनीतिक कदमों पर विचार किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को कम माइलेज के दर्द से राहत देने का सबसे तार्किक तरीका मूल्य प्रोत्साहन है। सरकार को ए20 या भविष्य के उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधनों की कीमत शुद्ध पेट्रोल या legacy फ्यूल की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत कम रखनी चाहिए। जब उपभोक्ता को ईंधन की कीमत में सीधी छूट मिलेगी, तो माइलेज की मामूली कमी की भरपाई आर्थिक रूप से हो जाएगी, और वे स्वेच्छा से पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का चयन करेंगे। जरुरत है सरकार और तेल विपणन कंपनियों को केवल दावों के बजाय प्रयोगशालाओं के प्रामाणिक डेटा को जनता के सामने रखना चाहिए। पुराने वाहनों की देखभाल कैसे करें, इथेनॉल ईंधन के उपयोग के दौरान किन सावधानियों को बरतें, इसके बारे में पेट्रोल पंपों पर ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। तथा खाद्यान्न और गन्ने पर निर्भरता कम करने के लिए पराली, बांस, और कबाड़ से बनने वाले सेकंड जनरेशन (2G) इथेनॉल के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करना होगा।

, भारत का इथेनॉल कार्यक्रम ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम है। समय से पहले ई20 के लक्ष्य को पाना सरकार के नीतिगत प्रबंधन की जीत है। लेकिन एक जीवंत लोकतंत्र और उपभोक्ता-प्रधान बाजार में किसी भी हरित क्रांति को टिकाऊ बनाने के लिए तकनीकी संवेदनशीलता और जन-आकांक्षाओं का आदर करना अनिवार्य होता है। सरकार ने ई25 पर कदम रोककर और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग जगत, नीति निर्माता और उपभोक्ता मिलकर एक ऐसा पारदर्शी तंत्र बनाएं, जहां देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिक की आर्थिक सुरक्षा दोनों एक साथ सह-अस्तित्व में समृद्ध हो सकें।

भिलाई में बनी इंडियन मेनोपॉज सोसायटी की 54वीं शाखा, महिलाओं में रजोनिवृत्ति संबंधी जागरूकता बढ़ाना है उद्देश्य

जे.एल.एन. अस्पताल में सीएमई और भिलाई मेनोपॉज सोसायटी का गठन समारोह संपन्न

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं रिसर्च सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सतत चिकित्सा शिक्षा सीएमई कार्यक्रम के साथ भिलाई मेनोपॉज सोसायटी का स्थापना एवं पदस्थापना समारोह आयोजित किया गया। यह सोसायटी इंडियन मेनोपॉज सोसायटी की देश की 54वीं शाखा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में मध्य आयु वर्ग की महिलाओं में रजोनिवृत्ति और महिला स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।

राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में इंडियन मेनोपॉज सोसायटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुधा शर्मा, जम्मू, प्रेसिडेंट-इलेक्ट डॉ. आरती गुप्ता, आगरा और राष्ट्रीय महासचिव डॉ. ज्योति जायसवाल, रायपुर मुख्य रूप से शामिल हुईं। इस अवसर पर सीएमओ प्रभारी डॉ. विनीता द्विवेदी, सीएमओ डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीना गुहा, जे.एल.एन. अस्पताल के विभागीय संकाय सदस्य, भिलाई के प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रायपुर मेनोपॉज सोसायटी के पदाधिकारी और आसपास के संस्थानों से आए लगभग 50 चिकित्सक उपस्थित रहे।

सीएमई में विशेष व्याख्यान

सीएमई सत्र में डॉ. ज्योति जायसवाल ने "General Elements in Menopause" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाले शारीरिक-मानसिक बदलाव, समय पर पहचान और उचित परामर्श-उपचार की जरूरत पर जोर दिया। डॉ. सुधा शर्मा ने इंडियन मेनोपॉज सोसायटी की स्थापना, उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन, जागरूकता, शोध और डॉक्टरों के प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभा रही है।

नई कार्यकारिणी गठित

समारोह में भिलाई मेनोपॉज सोसायटी की पहली कार्यकारिणी का गठन किया गया:
- संस्थापक अध्यक्ष: डॉ. निशा ठाकुर
- संस्थापक सचिव: डॉ. प्रभदीप कौर
- कोषाध्यक्ष: डॉ. हिमानी गुप्ता
- उपाध्यक्ष: डॉ. मोनीदीपा साहा
- संयुक्त सचिव: डॉ. श्वेता रानी प्रसाद

संस्थापक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों जे.एल.एन. अस्पताल से हैं। अन्य पदाधिकारी भिलाई व आसपास के विभिन्न अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सोसायटी के संचालन के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया है।

क्या है उद्देश्य

नवगठित सोसायटी विभिन्न अस्पतालों के विशेषज्ञों को एक मंच देगी ताकि पेरिमेनोपॉजल और मेनोपॉजल महिलाओं की समग्र स्वास्थ्य देखभाल हो सके। साथ ही रजोनिवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर जनजागरूकता बढ़ाकर महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता सुधारना इसका मुख्य लक्ष्य है। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

खास खबर

एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने 15 साल बाद छात्र राजनीति को कहा अलविदा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

2011 में कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था सफर, अब युवा कांग्रेस के जरिए करेंगे जनसेवा

छत्तीसगढ़ की छात्र राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने संगठन में अपने 15 वर्षों के सफर का भावुक अंदाज में समापन कर दिया है। सोनू साहू ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा कि 2011 में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति शुरू की थी। अब युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव के माध्यम से 2026 में नए अध्याय की शुरुआत के साथ ही NSUI की छात्र राजनीति का उनका सफर समाप्त हो रहा है।

15 साल में निभाई कई जिम्मेदारियां : सोनू साहू ने इन वर्षों में NSUI में विभिन्न पदों पर काम किया। 2014 में भिलाई विश्वविद्यालय, दुर्ग में कॉलेज अध्यक्ष बने। 2015 में बीसीईटी दुर्ग छात्रसंघ चुनाव में सचिव रहे। 2017 से 2019 तक दुर्ग जिला महासचिव, 2019 से 2021 तक दुर्ग जिला कार्यकारी अध्यक्ष रहे। इसी दौरान पाटन विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली। 2021 से 2026 तक वे NSUI छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2022 से 2026 तक बालोद और कांकेर जिला प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने का काम किया।

संगठन और साथियों का जताया आभार : अपने संदेश में सोनू साहू ने NSUI परिवार, कांग्रेस नेतृत्व, वरिष्ठजनों, साथियों और छात्र-छात्राओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन का यह अध्याय भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन युवा कांग्रेस के माध्यम से जनसेवा का उनका संकल्प हमेशा जारी रहेगा।

झांसा देकर 8 लाख की ठगी, दंपती गिरफ्तार

दुर्ग। भूमि विक्रय के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपियों ने एक ही भूमि का सौदा कई लोगों से कर उनसे ब्याना और उधारी के नाम पर लाखों रुपये ऐंठ लिए थे। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने थाना पुलगांव में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम दमोदा निवासी नोकेश देशमुख एवं नेहा देशमुख ने ग्राम अंजोरा स्थित खसरा नंबर 615/10, रकबा 0.0115 हेक्टेयर, प्लॉट नंबर-08 को 5.50 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया। इस दौरान प्रार्थी से ऑनलाइन एवं नकद माध्यम से 5.20 लाख रुपये तथा व्यवसायिक आवश्यकता बताकर उसकी माता से एनईएफटी के जरिए 2.80 लाख रुपये ले लिए। इस प्रकार आरोपियों ने कुल 8 लाख रुपये प्राप्त कर लिए, लेकिन भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में प्रार्थी ने ऑनलाइन भूइयां पोर्टल पर जांच की तो पता चला कि संबंधित भूमि पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। पुलिस विवेचना में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने इसी भूमि के नाम पर दीपक कुमार चौबे, दुर्गा शर्मा, दिनेश कुमार पाण्डे सहित अन्य लोगों से भी ब्याना राशि लेकर धोखाधड़ी की है। मामले की जांच के बाद पुलगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस ने प्रकरण से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य एवं बैंकिंग लेन-देन संबंधी अभिलेख भी जब्त किए हैं। साथ ही अन्य संभावित पीड़ितों और धोखाधड़ी से जुड़े तथ्यों की जांच जारी है।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधू, उप निरीक्षक बेदराम चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक पुष्पकराज, प्रधान आरक्षक शकुन्तला राठिया तथा सहायक उप निरीक्षक सुभाष साहू की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि की खरीद-बिक्री से पहले संबंधित दस्तावेजों एवं स्वामित्व का विधिवत सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाना या पुलिस हेल्पलाइन को दें।

'अटेंशन की होड़ में मिसलीडिंग खबरें गंभीर चिंता का विषय' : रजत बंसल

रायपुर प्रेस क्लब के 'हमर पहुना' कार्यक्रम में पहुंचे जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर प्रेस क्लब के 'हमर पहुना' कार्यक्रम में जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल और रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और पत्रकारों से संवाद किया तथा प्रेस क्लब के विकास, मीडिया की बदलती चुनौतियों और जनसंपर्क की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

रायपुर प्रेस क्लब के 'हमर पहुना' कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने कहा कि डिजिटल दौर में अटेंशन की होड़ ने पत्रकारिता के स्वरूप को बदल दिया है और मिसलीडिंग (भ्रामक) खबरों की बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा, "आज अटेंशन पाने का दौर है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा में कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जो भ्रामक होती हैं। अटेंशन के लिए हो रही पत्रकारिता का यह स्वरूप हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है।" रजत बंसल ने कहा कि सोशल मीडिया और न्यू मीडिया माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्वसनीय, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार, समाज और मीडिया तीनों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि सही और प्रमाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचे।

उन्होंने मीडिया से तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि बदलते दौर में विश्वसनीयता ही मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी है। पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रेस क्लब जैसी विश्वनीय संस्था से इस संबंध में आगे आने की अपील भी की

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार, एवं प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने कहा कि जनसंपर्क विभाग और पत्रकारिता एक-दूसरे के पूरक हैं। जनसंपर्क के माध्यम से शासन की योजनाएं और नीतियां समाज तक पहुंचती हैं, जबकि पत्रकार तथ्यपरक और संतुलित तरीके से उन्हें जनता के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच नियमित संवाद, पारदर्शिता और विश्वास का रिश्ता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है।

वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष बृजेश चौबे ने कहा कि पत्रकारों और जनसंपर्क विभाग के बीच बेहतर समन्वय, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और परस्पर सहयोग की भावना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ संवाद और विश्वसनीय सूचना व्यवस्था से न केवल मीडिया की साख मजबूत होती है, बल्कि शासन और आमजन के बीच भी प्रभावी संचार स्थापित होता है। ऐसे संवाद कार्यक्रम दोनों पक्षों के बीच विश्वास और सहयोग को और सुदृढ़ करने का माध्यम बनते हैं।

हमार पहुना कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने आज के डिजिटल युग में खबरे की तीव्रता के साथ-साथ भ्रम की धुंध फ्री फैलने की बात भी कही, उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों को नए माध्यमों में भी परंपरागत रूप से जिंदा रखने पर जोर दिया और पत्रकारिता में सच की लौ से भ्रम के जाल को काटने की पत्रकारों की असली जवाबदेही से काम करने की जरूरत की बात कही

इस अवसर पर महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित कायर्कारिणी सदस्य संदीप पुराणिक , जाकिर घुड़सेना , संतोष साहू चंदन साहू , नीरज मिश्रा, संजीव सिन्हा,

रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रामावतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा, विजय मिश्रा, यशवंत धोटे, प्रफुल्ल पारे, रवि भोई, राजेश जोशी, ,संजीव वर्मा, ई व्ही मुरली, समीर शुक्ला, संदीप तिवारी,मनीष वोरा, शंकर चंद्राकर, पप्पू फरिश्ता, प्रदीप चंद्रवंशी, विजय मिश्रा, प्रहलाद दमाहे, मनोज बघेल, चंद्रकांत दौंड़,रमेश पाण्डेय, विनय घाटगे जतिन नचरानी,मनोज बघेल, गिरीश केसरवानी, वरिष्ठ पत्रकार एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

डेंगू-मलेरिया से बचें, साफ-सफाई अपनाएं : महापौर मधुसूदन यादव

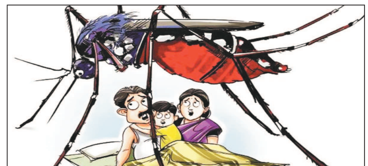

नागरिकों से घर-आसपास पानी जमा न होने देने की अपील, निगम अमले को विशेष सफाई के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए महापौर श्री मधुसूदन यादव ने नागरिकों से सावधानी बरतने और स्वच्छता अपनाने की अपील की है। महापौर ने कहा कि बरसात में मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए घरों एवं आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

नागरिकों से की ये अपील

महापौर श्री यादव ने कहा: पानी छानकर और उबालकर पिएं, खाद्य पदार्थों को ढककर रखें और ताजे फल-सब्जी का उपयोग करें।
- सर्दी-बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर इलाज कराएं।
- कूलर की नियमित सफाई करें और खस की शीट को कड़ी धूप में सुखाएं। डेंगू के मच्छर एडीज के अंडे खस की शीट में चिपके रहते हैं, नमी मिलते ही ये जीवित हो जाते हैं।
- आंगन और छत की पानी की टंकियों को ढककर रखें। टूटे-फूटे मटके, टायर-ट्यूब, प्लास्टिक बोतल, डब्बे नष्ट करें।
- फ्रिज की ट्रे और मंदिर के कलश का पानी हर सप्ताह बदलें। घरों के आसपास पानी जमा न होने दें।
- मच्छरदानी लगाकर सोएं।

उन्होंने कहा कि इन छोटी-छोटी सावधानियों से ही हम डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं।

निगम अमले को दिए निर्देश

महापौर ने नगर निगम के स्वास्थ्य अमले को भी निर्देश दिए कि प्रतिदिन नाली-नालों की सफाई और कचरा उठाव किया जाए। नियमित रूप से दवाई का छिड़काव हो। नल, हैंडपंप और गड्ढों में भरे पानी की निकासी के लिए कच्ची नाली खोदकर व्यवस्था की जाए। साथ ही टेमीफॉस और नुवान दवाई का छिड़काव कर लार्वा उत्पन्न होने से रोका जाए।

महासमुंद पुलिस की कार्रवाई :1700 किमी दूर तमिलनाडु से पकड़ा गया ओडिशा का गांजा तस्कर

मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, 12 लाख का 23 .790 किलो गांजा पहले ही जब्त

नई दृष्टिबिंदु / महासमुंद

जिले की खल्लारी पुलिस और सायबर टीम ने 1700 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में छिपे बैठे ओडिशा के गांजा सप्लायर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एंड टू एंड जांच कर मामले के मुख्य आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर महासमुंद लाकर न्यायालय में पेश किया।

क्या है मामला

थाना खल्लारी अपराध क्रमांक 19/2026, धारा 20(ख) NDPS एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। 17 फरवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लाल हीरो HF डीलक्स क्रमांक OD 03 AB 3511 में दो युवक ओडिशा के खरियार रोड से गांजा लेकर खल्लारी की ओर आ रहे हैं। NH 353 जोरातराई मोड़ में नाकाबंदी कर पुलिस ने अभिषेक यादव, निवासी दुर्ग और दीपक चंदन, निवासी दुर्ग को पकड़ा।

उनके कब्जे से प्लास्टिक बोरी में रखे 9 पैकेट में कुल 23 किलो 790 ग्राम गांजा कीमती करीब 12 लाख रुपये, एक मोटर सायकल 50 हजार और 2 मोबाइल 10 हजार रुपये जप्त किए गए। कुल जप्त संपत्ति 12 लाख 60 हजार रुपये की थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

1700 किमी दूर मिली दबिश

विवेचना में सामने आया कि गांजा ओडिशा के बसंता सुना, निवासी ग्राम भरूवामुंडा, जिला बलांगीर ने उपलब्ध कराया था। घटना के बाद से आरोपी फरार होकर ओडिशा से तमिलनाडु भाग गया था।

पुलिस अधीक्षक महासमुंद के निर्देशन में खल्लारी थाना और सायबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया। टीम ने तमिलनाडु के जिला तिरूपुर सिटी, थाना वीरापंडी, ग्राम वीरापंडी स्थित कली कुमार शामी कोविल ट्रस्ट में दबिश देकर 7 जुलाई 2026 को सुबह 9.20 बजे बसंता सुना को गिरफ्तार किया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर 9 जुलाई 2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश NDPS न्यायालय महासमुंद में पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

मुख्य सप्लायर बसंता सुना पिता लछी सुना, 30 वर्ष, निवासी ग्राम भरूवामुंडा, थाना बेलपड़ा, जिला बलांगीर, ओडिशा। हाल पता - कली कुमार शामी कोविल ट्रस्ट, ग्राम वीरापंडी, जिला तिरूपुर सिटी, तमिलनाडु।

पूर्व में गिरफ्तार परिवहनकर्ता

01. अभिषेक यादव, 22 वर्ष, निवासी डेली फार्म अंजोरा, दुर्ग

02. दीपक चंदन, 22 वर्ष, निवासी ग्राम कोहका, सुपेला, दुर्ग

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सोर्स से डेस्टिनेशन तक की कड़ी तोड़ने के लिए की गई। आरोपी से पूछताछ में और खुलासे की संभावना है।

एक करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प : आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा रायपुर प्रेस क्लब

जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल और निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने किया निरीक्षण, प्रस्तावित निर्माण कार्यों का लिया जायजा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राजधानी रायपुर के अनुरूप रायपुर प्रेस क्लब को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत एक करोड़ रुपये की राशि से प्रेस क्लब भवन के जीणीद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य जल्द प्रारंभ होगा। इसी क्रम में गुरुवार को जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल एवं रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने रायपुर प्रेस क्लब भवन का निरीक्षण कर प्रस्तावित निर्माण कार्यों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान प्रेस क्लब भवन की वतर्मान आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन किया गया तथा आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप निर्माण, इंटीरियर, साज-सज्जा एवं अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की गई। जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने वरिष्ठ पत्रकारों एवं प्रेस क्लब पदाधिकारियों से चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए, ताकि प्रेस क्लब को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा सके।

प्रस्तावित योजना के अनुसार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दो अत्याधुनिक सभागार, गेमिंग जोन, ड्राइंग/लाउंज हॉल, सुविधायुक्त शौचालय, आधुनिक इंटीरियर, बेहतर बैठक व्यवस्था , जीम हाल, लाइव डिस्कशन स्टूडियो तथा आकर्षक आउटर लैंडस्केपिंग विकसित की जाएगी। प्रेस क्लब में शुरू हो रहे हैं इस नवनिर्माण कार्य का उद्देश्य है कि राजधानी के पत्रकारों को एक आधुनिक, सुविधासंपन्न एवं गरिमामय कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। इस दौरान जनसंपर्क विभाग एवं रायपुर प्रेस क्लब के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने भी निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया।

रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने प्रेस क्लब की वर्तमान आवश्यकताओं एवं प्रस्तावित जीणीद्धार की विस्तृत जानकारी जनसंपर्क आयुक्त एवं निगम आयुक्त को दी। उन्होंने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब को राजधानी की गरिमा के अनुरूप आधुनिक स्वरूप प्रदान करना प्रेस क्लब की प्राथमिकता है और इसके लिए राज्य शासन द्वारा मिली स्वीकृति पत्रकार समुदाय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

निरीक्षण के दौरान रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित कायर्कारिणी सदस्य संदीप पुराणिक , जाकिर घुड़सेना , संतोष साहू चंदन साहू , नीरज मिश्रा, संजीव सिन्हा, रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, बृजेश चौबे, रामावतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा, विजय मिश्रा, यशवंत धोटे, प्रफुल्ल पारे, रवि भोई, राजेश जोशी, ,संजीव वर्मा, ई व्ही मुरली, समीर शुक्ला, संदीप तिवारी,मनीष वोरा, शंकर चंद्राकर, पप्पू फरिश्ता, प्रदीप चंद्रवंशी, प्रहलाद दमाहे, मनोज बघेल, चंद्रकांत दौंड़,रमेश पाण्डेय, जतिन नचरानी,मनोज बघेल, गिरीश केसरवानी, वरिष्ठ पत्रकार एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

राजामौली ने 'वाराणसी' को लेकर दी बड़ी अपडेट, फ्रेंचाइजी पर कही ये बात

एसएस राजामौली अपनी आगामी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चाओं में हैं। भले ही यह फिल्म अगले साल रिलीज होनी है, लेकिन घोषणा के बाद से ही फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच राजामौली शूटिंग से ब्रेक लेकर फ्रांस में हुए एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे, जहां उनकी फिल्में 'आरआरआर' और 'ईगा' दिखाई गईं। इसी दौरान राजामौली ने एक मास्टरक्लास में अपनी आने वाली फिल्म 'वाराणसी' को लेकर बात की और कन्फर्म किया कि 'बाहुबली' के उलट, यह फिल्म किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्टैंडअलोन फिल्म होगी।

फ्रेंचाइजी फिल्म नहीं होगी 'वाराणसी'

बातचीत के दौरान राजामौली ने बताया कि दर्शक 'वाराणसी' से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप अंटार्कटिका की ठंड और बर्फ का अनुभव करेंगे। रामायण के देवता, प्राकृतिक आपदाएं और शानदार तत्व यही सब अनुभव आपको मिलेगा, लेकिन इन सबके केंद्र में पिता और पुत्र की भावनाएं हैं। यही सब मिलकर आपके लिए 'वाराणसी' बनाते हैं। जब पूछा गया कि यह प्रोजेक्ट एक ही फिल्म होगी या फ्रैंचाइजी तो राजामौली ने जवाब दिया कि यह एक फिल्म है।

अगले साल रिलीज होगी फिल्म

एसएस राजामौली के निर्देशन और विजयेन्द्र प्रसाद की लिखी 'वाराणसी' में महेश बाबू, पृथ्वीराज और प्रियंका चोपड़ा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म माइथोलॉजी और भारतीय लोककथाओं को टाइम ट्रैवल जैसे साइंस-फिक्शन एलिमेंट्स के साथ मिलाकर एक ग्लोबल एडवेंचर बनाती है। फिल्म के एक सीक्वेंस में महेश बाबू भगवान राम के किरदार में भी नजर आएंगे। यह पूरा सीक्वंस रामायण पर आधारित होगा। राजामौली ने हाल ही में बताया था कि फिल्म के मुख्य एक्शन सीन पहले ही पूरे हो चुके हैं और अक्तूबर तक शूटिंग पूरी होने की उम्मीद है। यह फिल्म अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

'लॉकअप 2' में पहली वाइल्डकार्ड प्रतिभागी बनकर पहुंचीं शिल्पा शिंदे

'लॉकअप सीजन 2' में भरपूर ड्रामा देखने को मिल रहा है। प्रतिभागी अपनी जिंदगी से जुड़े नए-नए और दिलचस्प खुलासे कर रहे हैं। शो के इस ड्रामे में अब और भी तड़का लगने वाला है। शिल्पा शिंदे भी इस रियलिटी शो में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने पहली वाइल्डकार्ड प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया है। अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने रविवार को आधिकारिक तौर पर इस शो में एंट्री की। बता दें कि कुछ दिनों पहले शिल्पा शिंदे साल 2016 में 'भाभीजी घर पर हैं!' छोड़ने के बाद दर्ज कराई गई शोषण की शिकायत पर अपनी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रही थीं।

आत्मविश्वास से लबरेज दिखीं शिल्पा

'लॉकअप 2' को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। शो में खूब गरमागरम बहस, इमोशनल खुलासे हो रहे हैं। पहला एविक्शन हो चुका है। शिल्पा शिंदे के घर में पहली वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर आने से, कॉम्पिटिशन के एक और ड्रामैटिक मोड़ लेने की उम्मीद है। मेकर्स ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक प्रमोशनल वीडियो शेयर करके 'लॉकअप 2' में शिल्पा शिंदे की एंट्री की घोषणा की। क्लिप में वह कॉन्फिडेंस से कहती हैं, 'सुना है सब लोग अंदर अपनी-अपनी गाड़ी जमाए बैठे हैं। लेकिन उन्हें कह दो जब तक कोई बाहर का अंदर कदम नहीं रखता, तब तक ही उनका राज चलता रहेगा'।

गेम पलटने वाला है

सामने आए वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'सही पकड़े हैं! अब गेम पटलने वाला है'। बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर आने के बाद हुए विवाद के बाद शिल्पा की एंट्री हुई है। बातचीत के दौरान, उन्होंने टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर्स के साथ अपने झगड़े के बारे में बात की थी। बातचीत में शिल्पा शिंदे ने बताया था कि शो छोड़ने के बाद और बकाया पेमेंट को लेकर हुए झगड़े के बीच उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें बहुत फंसा हुआ महसूस हो रहा था और उन्होंने इस कदम को आखिरी रास्ता बताया। शिंदे ने यह भी कहा कि बाद में मामला सुलझ गया और उन्हें उनके बकाया पैसे मिल गए'।

प्रोड्यूसर पर लगाए थे झूठे आरोप

उन्होंने माना कि 'भाभीजी घर पर हैं!' के प्रोड्यूसर पर उन्होंने झूठे आरोप लगाए और वह इसलिए लगाए थे ताकि उन पर लगे आरोपों से ध्यान हटाया जा सके और कानूनी जांच से बचा जा सके। उनके मुताबिक, उन पर लगाए गए आरोप एक सोची-समझी मुहिम का हिस्सा थे, जिसका मकसद उन्हें कंट्रोल करना और शो छोड़ने पर इंडस्ट्री में काम पाने से रोकना था। उनकी इन बातों पर जल्द ही काफी बहस छिड़ गई और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनकी आलोचना की। बात करें, 'लॉकअप 2' की तो श्रेष्ठा अय्यर इस रियलिटी शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं। यह शो 27 जून को शुरू हुआ। शनिवार से बुधवार तक यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है।

नेटफ्लिक्स की नई रोमांटिक फिल्म 'मुसाफिर कैफे' में नजर आने वाले हैं विक्रांत मैसी

अभिनेता विक्रांत मैसी जल्द ही नेटफ्लिक्स की नई रोमांटिक फिल्म 'मुसाफिर कैफे' में नजर आने वाले हैं। निर्माताओं ने फिल्म का टीजर साझा किया। साथ ही निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। इस फिल्म में विक्रांत के साथ वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म 'मुसाफिर कैफे' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म में विक्रांत मैसी के साथ वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की पहली झलक शेयर की है। यह फिल्म 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

क्या है 'मुसाफिर कैफे' की कहानी

'मुसाफिर कैफे' की कहानी भोपाल और मसूरी की खूबसूरत जगहों पर आधारित है। यह तीन ऐसे अजनबियों की कहानी है, जिनकी जिंदगी आगे चलकर एक-दूसरे से जुड़ जाती है। यह फिल्म लेखक दिव्या प्रकाश दुबे के मशहूर उपन्यास पर आधारित है। इसे शरण्य राजगोपाल ने लिखा है और रुचिर अरुण ने निर्देशित किया है।

फिल्म के किरदार

विक्रांत मैसी फिल्म 'मुसाफिर कैफे' में चंदर के किरदार में नजर आएंगे। यह एक ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी का मकसद और सच्चाई ढूंढ रहा है। वेदिका पिंटो इस फिल्म में सुधा के रोल में नजर आएंगी। सुधा एक आजाद ख्यालों वाली लड़की है, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। महिमा मकवाना इस फिल्म में प्रीति के किरदार को निभा रही हैं। प्रीति एक शांत और समझदार लड़की, जो कहानी को आगे बढ़ाती है।

विक्रांत मैसी की आने वाली फिल्म

'मुसाफिर कैफे' के अलावा विक्रांत के पास कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। एक फिल्म में विक्रांत मशहूर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने कोलंबिया देश में 52 साल से चल रही आपसी लड़ाई को खत्म कराने और शांति लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

बॉलीवुड में उम्र के आधार पर भेदभाव पर ईशा कोप्पिकर ने उठाए सवाल

बॉलीवुड के कई सितारों ने ज्यादा उम्र के पुरुष कलाकारों के छोटी उम्र की अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करने के खिलाफ आवाज उठाई है। अब इसमें नया नाम एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर का जुड़ गया है। उन्होंने इंडस्ट्री में उम्र संबंधी भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। ईशा कोप्पिकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा 'यह बहुत अजीब है, है ना? एक आदमी की उम्र बढ़ने को अनुभव कहा जाता है, जबकि एक महिला की उम्र बढ़ने को समस्या। फिल्मों में हम हीरो को अपनी आधी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते देखते हैं। वे उनके हीरो बन जाते हैं। यह बहुत नॉर्मल है।'

महिला मजबूत होती है

उन्होंने आगे कहा 'अगर कोई महिला स्टाइलिश है, अपनी बात खुलकर रखती है और अपनी अलग पहचान को सेलिब्रेट करती है, तो उससे कहा जाता है कि इस उम्र में अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करो। सच तो यह है कि समय के साथ, एक महिला कम नहीं होती, वह और गहरी होती जाती है। उसका कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता। वह और मजबूत होता है। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं होती। यह उसके सफर में दिखती है। झुर्रियां सिर्फ उसकी उम्र नहीं दिखातीं, वे उसके संघर्षों को दिखाती हैं।'

जीवन के अनुभव देख सकते हैं

'कांटे' फिल्म की एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'आप उसमें उसकी हीलिंग और उसके जीवन के अनुभव को देख सकते हैं। अगर हर महिला को जीवन मिला है, तो उसकी उम्र बढ़ेगी ही। आपकी मां, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी और एक दिन आप खुद। हर किसी की उम्र बढ़ती है। इसलिए, उम्र बढ़ने को अपमान न बनाएं। हर उम्र में महिलाओं का सम्मान करें। उनकी उम्र न देखें, बल्कि उनके सफर को देखें। उनकी त्वचा न देखें, बल्कि उनकी ताकत को देखें। इसे समझें। क्योंकि गरिमा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कॉन्फिडेंस की कोई उम्र नहीं होती। इस बारे में सोचें।'

डॉ. अदिति गोवित्रिकर से साई पल्लवी तक; इन फिल्मी हस्तियों के पास है डॉक्टर की डिग्री

आपने कई फिल्मी सितारों को पर्दे पर डॉक्टर का किरदार निभाते देखा होगा। मगर, क्या आपको पता है कि फिल्मी दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं, जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है। इनमें से कुछ अब भी डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। चलिए जानते हैं...

अदिति गोवित्रिकर

आपने अदिति गोवित्रिकर को 'बाज', 'पहचान', 'हम कौन हैं?' जैसी फिल्मों में देखा होगा। मॉडलिंग की दुनिया में भी बड़ा नाम रहा। साल 2001 में मिसेज वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, लेकिन इन सबके पहले उनकी पहचान एक डॉक्टर की थी और दिलचस्प बात यह है कि इतने साल बाद भी वह पहचान उनसे कभी दूर नहीं हुई। खास बातचीत में अदिति ने बताया कि जिंदगी उन्हें फिल्मों तक जरूर ले आई, लेकिन लोगों की मदद करने का सपना आज भी वैसा ही है। अदिति आज भी लोगों के मेंटल हेल्थ से जुड़े मामलों पर काम कर रही हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर की पढ़ाई आज भी उनके हर दिन के काम का हिस्सा है।

श्रीलीला

आज तेलुगु फिल्मों का चर्चित चेहरा हैं। उन्होंने अभिनय के साथ-साथ एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और साल 2021 में डॉक्टर बनीं।

मेयांग चांग

मेयांग चांग को लोग गायक और अभिनेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन उन्होंने बेंगलुरु के वी. एस. डेंटल कॉलेज से बीडीएस की पढ़ाई की है और वह पेशे से दंत चिकित्सक रह चुके हैं।

मोहन आगाशे

मोहन आगाशे ने एमबीबीएस के बाद मनोचिकित्सा में एमडी किया था। फिल्मों में आने से पहले वह मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहे।

मानुषी छिल्लर

मानुषी छिल्लर फिल्मों में आने से पहले एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थीं। लेकिन साल 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया और मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई।

पलाश सेन

पलाश सेन को लोग बैंड यूफोरिया की वजह से जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एमबीबीएस किया है और वह हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं।

श्रीराम लागू

दिग्गज अभिनेता श्रीराम लागू ने पुणे के बी. जे. मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक ईएनटी सर्जन के तौर पर काम किया, फिर अभिनय की दुनिया चुन ली।

साई पल्लवी

साउथ सिनेमा का बड़ा नाम हैं। प्रेमम से पहचान बनाने वाली साई ने जॉर्जिया की त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है, हालांकि उन्होंने डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं की।

हैंडओवर से पहले ही स्कूल भवन में आई दरारें, 24 लाख की लागत वाले निर्माण की जांच की मांग तेज

समय रहते तकनीकी जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में बच्चों की सुरक्षा हो सकती है प्रभावित

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले के ग्राम मरका में लगभग 24 लाख रुपये की लागत से निर्मित शासकीय प्राथमिक शाला के नए भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। भवन का अभी विभाग को हैंडओवर भी नहीं किया गया है, लेकिन दीवारों में कई स्थानों पर दरारें दिखाई देने लगी हैं। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (आरईएस) द्वारा ग्राम मरका में शासकीय प्राथमिक शाला का नवीन भवन तैयार कराया गया है। हालांकि, भवन के औपचारिक हैंडओवर से पहले ही दीवारों में दरारें नजर आने लगी हैं। दरारों की तस्वीरें सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यह भवन छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है। ऐसे में शुरुआत में ही दीवारों में दरारें दिखाई देना चिंता का विषय है। उनका कहना है कि यदि समय रहते तकनीकी जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

मामले को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय साहू ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि भवन का हैंडओवर तभी किया जाना चाहिए, जब जांच में निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाए। यदि जांच में गुणवत्ता संबंधी लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान विभागीय इंजीनियरों द्वारा नियमित निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच का दावा किया जाता है। इसके बावजूद हैंडओवर से पहले ही भवन में दरारें आना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।

फिलहाल ग्रामीणों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्र तकनीकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है। विभाग की प्रतिक्रिया आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

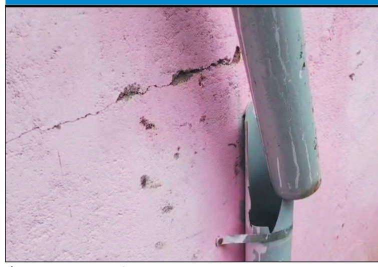

खास खबर

बारिश की चिंता हुई दूर, प्रधानमंत्री आवास योजना ने सुखदेव के परिवार को दिया सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

हर परिवार का सपना होता है कि उसके सिर पर एक सुरक्षित और मजबूत छत हो, जहाँ वह निश्चिंत होकर अपने भविष्य के सपने संजो सके। मानपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मरकेली निवासी सुखदेव निषाद के परिवार का यह सपना वर्षों तक अधूरा रहा। सीमित आय और आर्थिक तंगी के कारण वे जर्जर कच्चे खपरैल मकान में रहने को मजबूर थे। हर वर्ष बरसात का मौसम उनके लिए नई परेशानियाँ लेकर आता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि अब उनका परिवार सुरक्षित, सम्मानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है।

सुखदेव निषाद कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण.पोषण करते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती जानकी निषाद बताती हैं कि परिवार का कच्चा मकान मुख्य सड़क के किनारे होने के कारण बारिश के दिनों में सड़क का पानी सीधे घर में भर जाता था। पूरी रात परिवार के सदस्यों को जागकर पानी बाहर निकालना पड़ता था। घर की दीवारों में सीलन बनी रहती थी और बरसात के दौरान मकान के गिरने का भय भी हमेशा बना रहता था। उनकी पुत्री नंदिनी निषाद बताती हैं कि बारिश के दिनों में पढ़ाई करना बेहद कठिन हो जाता था। कई बार किताबें और जरूरी सामान भी भीग जाते थे।

श्रीमती निषाद कहती हैं कि सुरक्षित पक्के घर का सपना उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कभी पूरा होता दिखाई नहीं देता था। ऐसे समय में वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्का आवास स्वीकृत हुआ। योजना की सहायता से बना नया घर उनके परिवार के लिए केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और नए जीवन का आधार बन गया। पहले हर बारिश डर और चिंता लेकर आती थी। रातभर घर में पानी भरने की आशंका बनी रहती थी। अब पक्का घर मिलने के बाद वह डर पूरी तरह खत्म हो गया है। हमारी बेटी की पढ़ाई भी बिना किसी बाधा के हो रही है। सुखदेव निषाद एवं उनके परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत की है। आज उनका परिवार सुरक्षित घर में सम्मानपूर्वक रह रहा है।

स्थायी जाति प्रमाण पत्र निर्माण के लिए विकासखंडवार विशेष शिविरों का आयोजन

बेमेतरा। जिले में अध्ययनरत कक्षा पहली से 12वीं तक के ऐसे विद्यार्थियों, जिनका स्थायी जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बन पाया है, उनकी सुविधा एवं भविष्य में छात्रवृत्ति, प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विकासखंडवार विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निवास एवं आय प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विकासखंड नवागढ़ में 04 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक, विकासखंड साजा में 08 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक, विकासखंड बेरला में 11 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक तथा विकासखंड बेमेतरा में 11 जुलाई 2026 से 08 अगस्त 2026 तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों के आयोजन की स्थलवार एवं तिथिवार जानकारी जिले के सभी विद्यालयों को पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है। इन शिविरों में विद्यार्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिससे उन्हें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समयबद्ध रूप से प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके।

इस संबंध में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों, संबंधित राजस्व अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थल पर प्रातः 10 बजे से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर विद्यार्थियों के जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सुचारु एवं समयबद्ध ढंग से संपादित करना सुनिश्चित करें।

सौर ऊर्जा अपनाकर प्रेरणा स्रोत बने पंचायत सचिव

3-3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट से बिजली बिल में भारी बचत

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश के नागरिकों को स्वच्छ, सस्ती और आत्मनिर्भर ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बिजली के खर्चों को कम करने का एक बेहद प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है, जहाँ दो ग्राम पंचायत सचिवों ने खुद अपने घरों में सोलर प्लांट लगवाकर ग्रामीणों के सामने एक मिसाल पेश की है।

जनपद पंचायत छुरिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामपुर के सचिव रामलखन मण्डावी और ग्राम पंचायत जोंधरा के सचिव अर्जुन सिंह ठाकुर ने अपने-अपने निजी आवासों पर 3-3 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाए हैं। दोनों सचिवों की यह अनूठी पहल न केवल उनके घरों में आर्थिक बचत का जरिया बनी है, बल्कि आसपास के लोगों को भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

पूरी प्रक्रिया है सरल और पारदर्शी

योजना के लाभ और अपने अनुभवों को साझा करते हुए रामपुर के सचिव रामलखन मण्डावी ने बताया कि उन्होंने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था। विद्युत विभाग से आवश्यक तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद, विभाग द्वारा अधिकृत विक्रेता (वेंडर) के माध्यम से उनके घर की छत पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट और नेट मीटर सफलतापूर्व स्थापित कर दिया गया।

मिली 1.08 लाख की भारी सब्सिडी

इस योजना की सबसे खास बात इसकी वहन करने योग्य लागत है। दोनों ही सचिवों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलाकर कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई है, जिससे प्लांट लगाने की शुरुआती लागत (इन्स्टॉलेशन कॉस्ट) काफी कम हो गई।

बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण

श्री मण्डावी ने बताया कि अब उनके घर की बिजली से जुड़ी अधिकांश जरूरतें सौर ऊर्जा से ही पूरी हो रही हैं, जिससे हर महीने आने वाले बिजली बिल में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही, जरूरत से ज़्यादा उत्पादित होने वाली अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने पर उन्हें 'नेट मीटरिंग' का दोहरा लाभ भी मिल रहा है। इसी तरह जोंधरा पंचायत के सचिव अर्जुन सिंह ठाकुर ने भी पूरी प्रक्रिया की सराहना करते हुए इसे बेहद सरल, सहज और पारदर्शी बताया। उन्होंने इस जनहितैषी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

आत्मनिर्भर बनने की अपील

दोनों पंचायत (ग्राम पंचायत जोंधरा, ग्राम पंचायत रामपुर) सचिवों ने आम नागरिकों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं और 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाकर न केवल बिजली के खर्चों से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

जिले में अब तक 1739.7 मिमी वर्षा दर्ज, आज 29.4 मिमी बारिश हुई

राजनांदगांव। जिले में इस वर्ष चालू मानसून वर्ष में 1 जून 2026 से अब तक जिले के सभी 7 तहसीलों में 1739 .7 मिमी बारिश एवं औसत 248 .5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी अनुसार डोंगरगढ़ तहसील में 285 .9 मिमी, लाल बहादुर नगर तहसील में 291 मिमी, राजनांदगांव तहसील में 337 .3 मिमी, घुमका तहसील में 124 मिमी, छुरिया तहसील में 204 .8 मिमी, कुमरदा तहसील में 265 .7 मिमी, डोंगरगांव तहसील में 231 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अब तक सर्वाधिक वर्षा राजनांदगांव तहसील में 337 .3 मिमी दर्ज की गई है। इसी तरह राजनांदगांव जिले के सभी 7 तहसीलों में 29 .4 मिमी एवं औसत 4 .2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। डोंगरगढ़ तहसील में 10 .5 मिमी, लाल बहादुर नगर तहसील में 1 .5 मिमी, राजनांदगांव तहसील में 4 .7 मिमी, घुमका तहसील में 2 मिमी, छुरिया तहसील में 4 मिमी, कुमरदा तहसील में 6 .4 मिमी, डोंगरगांव तहसील में 0 .3 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा डोंगरगढ़ तहसील में 10 .5 मिमी दर्ज की गई है।

शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता, विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए करें समयबद्ध कार्य-कलेक्टर तुलिका

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी योगदास साहू, तीनों विकास खंड के शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभागीय कमर्चारी उपस्थित रहें।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने अपार आईडी एंट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति एवं प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन कर ऐसे विद्यालयों को सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित करने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए अभी से बेहतर कार्ययोजना बनाकर विद्यार्थियों की नियमित शैक्षणिक मॉनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मासिक टेस्ट के माध्यम से कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दे।

कलेक्टर ने वीएसके ऐप एवं बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज हो रही उपस्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने जाति, निवास एवं आधार कार्ड से वंचित विद्यार्थियों की जानकारी लेकर सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रभावी रणनीति अपनाने को कहा। वहीं नशाखोरी अथवा अनुशासनहीनता में लिप्त शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

बिहान से बदली तकदीर, सुनीता बनीं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायी मिसाल

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

जिले के विकासखंड खैरागढ़ अंतर्गत ग्राम टेकापारकला की निवासी सुनीता वर्मा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायी मिसाल बन चुकी हैं। कभी खेती-किसानी और मजदूरी के सहारे परिवार का भरण-पोषण करने वाली सुनीता वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी और आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की, जो आज क्षेत्र की अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

वर्ष 2017 में पद्म मां गायत्री स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई। समूह के माध्यम से प्राप्त प्रथम ऋण राशि 5 हजार रुपये से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और बैग सिलाई का कार्य प्रारंभ किया। यह छोटा प्रयास आगे चलकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव साबित हुआ। इसके बाद प्राप्त 5 लाख रुपये के ऋण से उन्होंने 48 डिसमिल कृषि भूमि और ट्रैक्टर खरीदा, जिससे कृषि कार्य का विस्तार हुआ तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। बाद में 3 लाख रुपये के ऋण से ट्रॉली खरीदकर कृषि एवं परिवहन कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया।

आज सुनीता वर्मा कृषि आधारित उद्यमिता के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। वे हल्दी, धनिया और मिर्च जैसी मसाला फसलों की खेती कर स्वयं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एवं मिर्च पाउडर तैयार करती हैं। इसके साथ ही अचार, बड़ी और पापड़ का निर्माण एवं पैकेजिंग कर सी-मार्ट, सरस मेला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त ऑर्डर के अनुसार विक्रय करती हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में आयोजित क्षेत्रीय सरस मेलों में भाग लेकर वे अपने उत्पादों का विपणन करती हैं, जिससे उन्हें बेहतर आय प्राप्त हो रही है। मसाला एवं खाद्य उत्पादों के निर्माण और विक्रय से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त होती है।

कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्तमान में वे लगभग सात एकड़ भूमि किराये पर लेकर धान, गेहूं, चना, अरहर, मूंग, उड़द तथा विभिन्न सब्जियों की खेती कर रही हैं। कृषि कार्य से लागत निकालने के बाद उन्हें प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त वे पिछले तीन वर्षों से ई-रिक्शा संचालन से भी जुड़ी हुई हैं। सृजन संकुल संगठन से किराये पर प्राप्त ई-रिक्शा के संचालन से उन्हें नियमित अतिरिक्त आय मिल रही है।

वर्ष 2025 से उन्होंने सब्जी नसर्री तैयार करने का कार्य भी शुरू किया, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। विविध आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आज उनकी वार्षिक आय लगभग चार लाख रुपये तक पहुंच गई है। सुनीता वर्मा की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने खैरागढ़-छुईखदान मुख्य मार्ग पर अपना पक्का मकान एवं दुकान भी स्थापित किया है। वर्तमान में वे अपनी दुकान से स्वयं निर्मित मसाले, अचार, बड़ी और पापड़ का विक्रय कर रही हैं। साथ ही दुकान में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का संचालन कर ग्रामीणों को विभिन्न डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। सुनीता वर्मा का संघर्ष और सफलता यह सिद्ध करता है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और आर्थिक सहयोग मिले तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। आज वे अपने गांव और आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी हैं। भविष्य में वे पशुपालन गतिविधि प्रारंभ कर अपने व्यवसाय को और विस्तारित करने की योजना बना रही हैं। बिहान योजना के सहयोग और अपनी अथक मेहनत के बल पर सुनीता वर्मा ने आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी कहानी लिखी है, जो ग्रामीण विकास की दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती व एनीमिक महिलाओं के घरों में मुनगा पौधों का रोपण

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण और महिलाओं एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। भारत सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 7 जुलाई 2026 से जिले में गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती एवं एनीमिक महिलाओं के घरों में मुनगा (मोरिंगा) के पौधों का रोपण कर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

यह अभियान जिला कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), महिला एवं बाल विकास विभाग, बेमेतरा द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं एनीमिक महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करना, घर-घर पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जनभागीदारी के माध्यम से कुपोषण को दूर करना है।

अभियान के दौरान विभागीय टीम द्वारा हितग्राहियों के घरों में मुनगा के पौधे रोपे जा रहे हैं तथा उनके परिवारजनों को पौधों की देखभाल एवं नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही संतुलित एवं पौष्टिक आहार, स्वच्छता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा एनीमिया से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है।

कार्यक्रम में बताया गया कि मुनगा को सुपोषण का पौधा माना जाता है। इसकी पत्तियां, फलियां और फूल प्रोटीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम सहित अनेक आवश्यक खनिजों एवं एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कुपोषण एवं एनीमिया की समस्या में सुधार होता है, रक्त शकर्रा एवं रक्तचाप नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है तथा पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके अलावा हृदय स्वास्थ्य में सुधार, सूजन एवं जोड़ों के दर्द में राहत, मानसिक तनाव में कमी तथा त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी मुनगा अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

विभागीय अधिकारियों ने हितग्राहियों से अपने घरों एवं आसपास अधिक से अधिक मुनगा के पौधे लगाने तथा दैनिक भोजन में इसकी पत्तियों एवं फलियों का नियमित उपयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित परिवारों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने और पोषण संबंधी सुझावों का पालन करने का संकल्प भी लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग का यह अभियान जिले में कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार तथा पोषण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल साबित हो रहा है। विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी जिले के विभिन्न ग्रामों एवं आंगनबाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के जागरूकता एवं पौधारोपण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

खनिज न्यास निधि से प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण को मिली 16.27 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति

जिले में शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने एवं विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) की प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्ष सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत मनोधरपुर (मेहना) स्थित प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 16 लाख 27 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्माण कार्य जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) निधि से कराया जाएगा। अतिरिक्त कक्ष बनने से विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त एवं सुविधाजनक अध्ययन कक्ष उपलब्ध होंगे, जिससे शिक्षण व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बन सकेगी। साथ ही बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप आवश्यक अधोसंरचना विकसित होने से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत कार्य को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस स्वीकृति से क्षेत्र के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों में उत्साह का माहौल है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण कार्य की आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी ऐरिना कैपीटल का संचालक हुआ गिरफ्तार

सुपेला पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी योगेश साहू को भेजा जेल

निवेश पर दोगुनी राशि का झांसा देकर कई निवेशकों से की ठगी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर राशि दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले ऐरिना कैपीटल के संचालक योगेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। थाना सुपेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

क्या है पूरा मामला

थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 961/2026 धारा 318(2), 318(4), 61(2) इटर के तहत मामला दर्ज है। प्रार्थी राजू नामदेव, निवासी मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला ने 8 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई कि ऐरिना कैपीटल के संचालक और सहयोगियों ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश कराने और अधिक लाभ देने का वादा कर उनसे 15 लाख रुपये निवेश कराए। शुरुआत में विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ लाभ दिया गया, लेकिन बाद में लाभ देना और मूल राशि लौटाना भी बंद कर दिया।

विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने इसी तरीके से कई अन्य निवेशकों से भी करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोपी के खिलाफ सुपेला और स्मृति नगर चौकी में पहले से कई धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं।

स्मृति नगर में था कार्यालय

आरोपी ने सड़क क्रमांक-24, स्मृति नगर स्थित ऐरिना कैपीटल कार्यालय के माध्यम से निवेशकों को झांसे में लिया। पुलिस को विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद फरार आरोपी योगेश साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया, थाना पाटन, हाल पता पामवुड रेसिडेंसी, कातुलबोर्ड, थाना मोहन नगर को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है। इस कार्रवाई में फिलहाल कोई अलग से सामग्री जप्त नहीं की गई है।

पुलिस टीम की भूमिका

गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सुपेला अंबर भारद्वाज, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक अमर सिंह और आरक्षक प्रदीप सिंह की अहम भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति के निवेश प्रस्ताव पर पैसा लगाने से पहले उसकी वैधानिकता और प्राधिकृत पंजीयन का सत्यापन जरूर करें। अवास्तविक लाभ या राशि दोगुनी करने जैसे प्रलोभनों से सावधान रहें। वित्तीय धोखाधड़ी की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

2 प्रतिशत DA, कैशलेस चिकित्सा, 300 दिन अवकाश नगदीकरण सहित अन्य मांगें

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ दुर्ग के पदाधिकारियों ने बुधवार को क्षेत्र में प्रवास पर आए सांसदों और विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता सहित 6 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

क्या हैं प्रमुख मांगें: संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि "मोदी की गारंटी" के तहत कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं को लागू किया जाए।

महंगाई भत्ता: केंद्र की तिथि 1 जनवरी 2026 से 2% DA राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं को दिया गया है। प्रदेश के 4.50 लाख अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को भी देय तिथि से DA/DR दिया जाए और एरियर्स की राशि GPF खाते में समायोजित की जाए।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा: बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद भी अभी तक नियम-निर्देश जारी नहीं हुए। कर्मचारियों के हित में आदेश तत्काल जारी किया जाए।

अवकाश नगदीकरण: केंद्रीय कर्मचारियों और अविभाजित मध्यप्रदेश की तरह सेवानिवृत्ति पर 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण का आदेश जारी हो।

नियमितीकरण: संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा मध्यप्रदेश की तरह सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

शिक्षक LB संवर्ग: प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर शिक्षक LB संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जाए।

अनुकंपा नियुक्ति: अनुकंपा नियुक्ति में लगी 10 प्रतिशत की सीलिंग समाप्त की जाए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेश चटर्जी शिक्षक फेडरेशन, विजय लहरे प्रांतीय महामंत्री, प्रदीप चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिवदयाल धृतलहरे जिला सचिव, सुखेन्द्र देवांगन, व्ही.एस.राव, सुरेश साहू, डी.एस.भारद्वाज, पंकज राठौर, मोतीराम खिलाड़ी, निमर्ला रात्रे, संजय साहू, चतुर यादव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

रोमानिया में आयोजित गोल्डन बेल्ट आमंत्रण मुक्केबाजी में छत्तीसगढ़ के तीरथ राउत जज-रेफरी नियुक्त

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया मनोनयन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

रोमानिया में 9 से 18 जुलाई 2026 तक होने वाले गोल्डन बेल्ट आमंत्रण मुक्केबाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के तीरथ राउत को जज/रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एशियन कन्फेडरेशन के रेफरी/ज तीरथ राउत को इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मनोनीत किया गया है। तीरथ राउत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 8 जुलाई को रवाना हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष आर. राजेंद्रन ने तीरथ राउत के चयन पर बधाई देते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने संघ के सभी पदाधिकारियों की ओर से तीरथ राउत को शुभकामनाएं दीं।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100